● वर्ष-5
● अंक-199
रायपुर, मंगलवार
07 अप्रैल 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› प्रदेश की धरती के कण-कण में...

कोच्चि में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत

राष्ट्र की समृद्धि ही व्यक्तिगत प्रगति की कुंजी है: मोहन भागवत

कोच्चि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि व्यक्तिगत समृद्धि केवल तभी प्राप्त की जा सकती है, जब देश समृद्ध और सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्तिगत प्रगति को देश की प्रगति से जोड़ना आवश्यक है। आरएसएस प्रमुख ने यह बात कोच्चि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध छात्रों के सांस्कृतिक संगठन बालागोकुलम के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कही। मोहन भागवत ने जोर देकर कहा कि समृद्धि और सुरक्षा को अलग-अलग हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, जब देश समृद्ध और सुरक्षित होता है, तभी परिवार भी समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त करते हैं। जब व्यक्ति राष्ट्र की समृद्धि और सुरक्षा के लिए काम करते हैं, तो वे स्वयं भी समृद्ध होते हैं। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि लोगों को अक्सर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत करियर विकास और देश के विकास के लिए काम करने के बीच चयन को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि करियर निर्माण और राष्ट्र के लिए काम करना परस्पर विरोधी नहीं हैं।उन्होंने कहा, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि करियर बनाना और राष्ट्र के लिए काम करना विरोधाभासी नहीं हैं। कुंजी सही मार्ग चुनने में निहित है। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के हिस्से के रूप में मोहन भागवत ने भगवान कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने बालागोकुलम कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों के साथ भी बातचीत की।

राष्ट्र निर्माण में व्यक्तिगत भूमिका

मोहन भागवत ने जोर देकर कहा कि समृद्धि और सुरक्षा को अलग-अलग हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, जब देश समृद्ध और सुरक्षित होता है, तभी परिवार भी समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त करते हैं। जब व्यक्ति राष्ट्र की समृद्धि और सुरक्षा के लिए काम करते हैं, तो वे स्वयं भी समृद्ध होते हैं। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि लोगों को अक्सर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

युवाओं के लिए मार्गदर्शन

युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत करियर विकास और देश के विकास के लिए काम करने के बीच चयन को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि करियर निर्माण और राष्ट्र के लिए काम करना परस्पर विरोधी नहीं हैं।

उन्होंने कहा, 'इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि करियर बनाना और राष्ट्र के लिए काम करना विरोधाभासी नहीं हैं। कुंजी सही मार्ग चुनने में निहित है।' सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के हिस्से के रूप में मोहन भागवत ने भगवान कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने बालागोकुलम कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों के साथ भी बातचीत की।

असम की चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी

'कांग्रेस ने वही गीत गाया जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की'

नई दिल्ली। चुनावी राज्य असम के बारपेटा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोदी को नीचा दिखाने के लिए सेना के शौर्य को भी गाली देती है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक होज हमने देखा है कि कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के एजेंडे को हवा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर टिकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था और पाकिस्तान को पसंद है।

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का ये पाकिस्तान कनेक्शन हमेशा देश पर भारी पड़ता है। कांग्रेस ने हमारी फौज से कैसे विश्वासघात किया है, इसका एक उदाहरण, वन रैंक और वन पेंशन भी है। कांग्रेस ने 500 रुपये दिखाकर कहा था कि वो ह्रक्रह्रक्र लागू करेगी, ये बीजेपी सरकार है जिसने बीजेपी

का लाभ मेरे फौजी भाइयों को दिया।

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का साथ दे रही है। कांग्रेस, अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रही है। कांग्रेस असम में ऐसा कानून बनाने की बात भी कर रही है जिसके बाद घुसपैठिया शब्द बोलने वाले को भी जेल हो जाएगी। कांग्रेस, कानून में ही घुसपैठियों को पीड़ित घोषित कर देगी।

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए संकीर्ण दृष्टिकोण अपना रही है, जबकि भाजपा की योजना दीर्घकालिक विकास की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सत्ता केवल कुछ राज्यों में बची है, वे काम का ब्योरा नहीं देते पर भाजपा किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। भाजपा नीत राजग किसानों की पहली पसंद है, गठबंधन ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को सीधे बैंक खातों में लाभ का अंतरण हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सत्ता केवल कुछ राज्यों में बची है, वे काम का ब्योरा नहीं देते पर भाजपा किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने से इनकार करके सेना के साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रही है, इस संबंध ने देश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला संगठन-सूत्र है भाजपा: साय

रायपुर। 47 वें स्थापना दिवस पर भाजपा ने सोमवार से विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की।इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी का पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने भाजपा के पितृ पुरूषों के प्रतिमाओं को नमन कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम साय ने कहा कि यह किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला संगठन-सूत्र है। भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठाएँ और भारत को परम वैभव के शिखर पर स्थापित करने का संकल्प और साथ ही यह आत्मविश्वास कि अपने पुरुषार्थ से हम इस लक्ष्य को अर्जित करेंगे। आज के दिन भाजपा कार्यकर्ता देशभर में सेवा और समर्पण के कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन की सेवा में जुटे हैं।

राज्यसभा में 19 सांसदों ने ली शपथ

नईदिल्ली। भारतीय संसदीय इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। राज्यसभा के सभापति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज राज्यसभा कक्ष में नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित 19 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह का मुख्य आकर्षण मशहूर संवैधानिक वकील डॉ मेनका गुरुस्वामी रहीं। उन्होंने पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद के रूप में शपथ लिया। मेनका गुरुस्वामी देश की पहली ऐसी सांसद हैं, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान एक क्वीर के रूप में साझा की है।

कानूनी लड़ाई से संसद तक का सफर: 51 वर्षीय डॉ मेनका गुरुस्वामी का राज्यसभा पहुंचना सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे संस्थानों से शिक्षित गुरुस्वामी को साल 2018 की उस ऐतिहासिक कानूनी जीत के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में धारा 377 के खिलाफ लड़ाई लड़कर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करवाया था। टीएमसी ने अपनी रणनीति के तहत उन्हें उच्च सदन भेजा है ताकि संसद में संवैधानिक मूल्यों और

नागरिक अधिकारों की आवाज को मजबूती दी जा सके। शपथ लेने के बाद गुरुस्वामी ने दोहराया कि वह संविधान के समानता और भेदभाव रहित मूल्यों को आगे बढ़ाएंगी।

इन 19 सांसदों ने ली शपथ: समारोह के दौरान कुल 19 सदस्यों ने शपथ ली, जिनमें राजनीति के दिग्गज और नए चेहरे दोनों शामिल रहे। शपथ लेने वाले सदस्यों में रामदास बंधु आठवले, माया चिंतामन इवनाते, शरदचंद्र पवार,रामराव सखाराम वडकुते, डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे,क्रिस्टोफर मणिकम, डॉ अंबुमणि रामदास, कॉन्सटेंटाइन रवींद्रन, एल के सुधीश, डॉ एम थंबीदुरई, तिरुचि शिवा, बाबुल सुप्रिया बराल, डॉ मेनका गुरुस्वामी, राजीव कुमार, रुक्मिणी मलिक (कोयल मलिक), बिस्वजीत सिन्हा, संतृप्त मिश्रा,

दिलीप कुमार रे और मनमोहन सामल शामिल हैं।

क्षेत्रीय विविधता की झलक

आज के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की विविधता में एकता की स्पष्ट झलक देखने को मिली। कुल 19 सदस्यों में से 6 सदस्यों ने तमिल में, 4 ने बंगाली में, 3 ने मराठी में, 3 ने ओडिया में, 2 ने हिंदी में और 1 सदस्य ने अंग्रेजी में शपथ ली। इस बार राज्यसभा में तमिलनाडु से 6, महाराष्ट्र से 5, पश्चिम बंगाल से 5 और ओडिशा से 3 सदस्य चुनकर आए हैं। इस अवसर पर संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, जनजातीय कार्य मंत्री जुअल ओराम, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी और सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रमुख समाचार

एनडीए को मिल रहा अपार जनसमर्थन: जेपी नड्डा

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा कि असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में मजबूत माहौल है। तिनसुकिया में एएनआई से बात करते हुए नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के पक्ष में माहौल है। एनडीए को समाज के सभी वर्गों का सर्वसम्मति से समर्थन मिल रहा है। मोदी जी ने असम में जो काम

किया है, असम को जो आशीर्वाद दिया है और हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने जमीनी स्तर पर जिस तरह से इसे लागू किया है, असम की जनता उसका स्वागत कर रही है। असम में 9 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होंगे और मतगणना 4 मई को होगी। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि उसने अपने हितों को प्राथमिकता दी और अपने शासनकाल में असम को विकास से वंचित रखा। भाजपा उम्मीदवार शिलादित्य देव के समर्थन में होजाई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, मोदी ने जिले में बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए एनडीए सरकार के प्रयासों की सराहना की।

दिल्ली से चलती है पुडुचेरी की सरकार : राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि पुडुचेरी सरकार दिल्ली से थोपी गई है और यह क्षेत्र की जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उन्होंने भाजपा पर पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में विफल रहने और केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने

का भी आरोप लगाया। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, पुडुचेरी में मतदान 9 अप्रैल को होना है और मतगणना 4 मई को होगी। पुडुचेरी की 30 सदस्यीय विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है। लॉस्पेट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पुडुचेरी की सरकार पुडुचेरी की जनता की राय नहीं है, बल्कि दिल्ली से थोपी गई है। पूर्ण राज्य का दर्जा हमेशा से एक मुद्दा रहा है, जिसका वादा भाजपा ने किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। भाजपा चाहती है कि पुडुचेरी श्री अडानी के स्वामित्व में रहे। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कराईकल को पहले ही उन्हें बेचा जा चुका है। सब जानते हैं कि सभी ठेकों पर 30 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है।

सियासी विवाद: गुजरात के लोग अनपढ़: खड़गे

इडुक्की मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरलम में चुनावी रैली के दौरान एक बयान देकर सियासी विवाद खड़ा कर दिया. उन्होंने गुजरात के लोगों को अशिक्षित बताते हुए कहा कि वहां के लोगों को नरेंद्र मोदी आसानी से गुमराह कर सकते हैं, लेकिन केरल के लोग ज्क्यादा समझदार और शिक्षितक्क हैं, इसलिए

उन्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता. इडुक्की में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पिनरायी विजयन दोनों एक ही राह पर चल रहे हैं और उनके बीच सिर्फ पार्टी का फर्क है.उन्होंने आरोप लगाया कि विजयन परोक्ष रूप से मोदी के नियंत्रण में काम कर रहे हैं. खड़गे के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है. विपक्षी दलों ने इसे अपमानजनक बताते हुए प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि केरल की 140 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके चलते सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है. मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने तीखा हमला बोला।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज

नईदिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 193 सांसदों द्वारा पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है. सभापति ने प्रस्ताव के सभी पहलुओं का निष्पक्ष मूल्यांकन किया. न्यायाधीश (जांच) अधिनियम की शक्ति का प्रयोग करते हुए इसे अस्वीकार कर

दिया. अब मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल सुरक्षित है. 12 मार्च को राज्यसभा में पेश किए गए इस प्रस्ताव पर राज्यसभा के सभापति ने गंभीर विचार-विमर्श किया. सभी प्रासंगिक पहलुओं और मुद्दों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के बाद, सभापति ने न्यायाधीश अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया. इस निर्णय के बाद साफ हो गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जारी रहेगा और उनके खिलाफ महाभियोग की कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। यह कदम संविधान और चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस दिया था।

ईवीएम मशीनों की सुरक्षा पर नजर रखें: ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ दिनों में वोटिंग होने वाली है। उससे पहले प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईवीएम को लेकर मुर्शीदाबाद की रैली

में बूथ एजेंटों और मतदाताओं से सतर्क रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि सभी लोग ईवीएम मशीन को अच्छे से चेक करें और जो बूथ एजेंट बनेंगे, वे अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि बंगाल के हित में काम करें। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति बीजेपी के सामने बिके नहीं। मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि ईवीएम में मौजूद सभी बटन को दबाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वोट सही जगह दर्ज हो रहा है या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर ईवीएम मशीन को खराब करने की योजना बनाई जाती है, इसलिए अगर मशीन खराब हो तो उसे ठीक कराने की बजाय नई मशीन मंगाने की मांग करनी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस

भाजपा : एक आंदोलन की गाथा, एक राष्ट्र का संकल्प

तरुण चुघ

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केवल एक राजनीतिक दल नहीं, यह उस विचार की जीवंत अभिव्यक्ति है जो सदियों से इस देश की आत्मा में बसा है-राष्ट्र सर्वोपरि है, अंत्योदय हमारा धर्म है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी पहचान है। जब 6 अप्रैल, 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो यह केवल एक नए राजनीतिक संगठन का जन्म नहीं था, यह उन करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं का संगठन था, जो चाहते थे कि इस देश की राजनीति में ईमानदारी हो, विचार हो और राष्ट्र के प्रति समर्पण हो। आज जब हम अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो यह अवसर केवल उत्सव का नहीं, बल्कि उस यात्रा के स्मरण और उस संकल्प के नवीनीकरण का है, जिसने भाजपा को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया। भाजपा की वैचारिक जड़ें उस मिट्टी में हैं, जिसे पं. दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन के रूप में सींचा। दीनदयाल जी ने यह स्पष्ट किया था कि भारत की राजनीति का केंद्र ड्क्षबदू वह अंतिम व्यक्ति होना चाहिए, जो समाज की सबसे निचली पायदान पर खड़ा है। अंत्योदय की यह परिकल्पना भाजपा के लिए कोई चुनावी नारा नहीं, बल्कि एक जीवन-दर्शन है।

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना से लेकर कश्मीर के लिए अपने प्राणों की आहुति देने तक, यह सिद्ध किया कि राष्ट्रीयता का अर्थ केवल वोट की राजनीति नहीं, बल्कि मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की तत्परता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विचार को जन-जन तक पहुंचाया। उनकी वाणी में कविता थी, उनके कार्य में दृष्टि थी और उनके नेतृत्व में भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में विश्वपटल पर स्थापित करने का साहस था। लाल कृष्ण अडवानी जी ने रथयात्रा निकाली तो सिर्फ मंदिर आंदोलन नहीं जगाया, उन्होंने उस समाज को जगाया, जो दशकों से अपनी ही भूमि पर उपेक्षित था।

1984 में देश में सहानुभूति की लहर में भाजपा को केवल 2 सीटें मिलीं, तो कई लोगों ने इस दल को इतिहास की धूल में दफन समझ लिया था। लेकिन उस पराजय ने भाजपा के कार्यकर्त्ताओं को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत किया। बूथ से लेकर राष्ट्र तक संगठन की नींव रखी गई, कार्यकर्त्ताओं ने मेहनत की पराकाष्ठा की और फिर वह दिन आया, 2014, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने 282 सीटें जीतीं, 3 दशक बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और भारत की राजनीति का कायाकल्प हो गया। 2019 में 303 सीटों के साथ यह सिद्ध हो गया कि यह लहर नहीं, जनता का स्थायी विश्वास है। 2024 में एन.डी.ए. के साथ तीसरी बार सत्ता में आना यह प्रमाण है कि भारत की जनता ने भाजपा को अपनी नियति के साथ जोड़ लिया है। आज भाजपा 15 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है।

मोदी जी ने एक नई शासन संस्कृति की नींव रखी, न तुष्टीकरण, न परिवारवाद, न भ्रष्टाचार। उनका मंत्र था-सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पिछले 12 वर्षों में जो काम हुआ है, वह भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। 500 वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हुआ। 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और करोड़ों हिंदुओं की आंखें छलक उठीं। एक और काम जो दशकों से लंबित था, माननीय अमित शाह जी की दृढ़ इच्छाशक्ति और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 5 अगस्त, 2019 को संसद में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग संवैधानिक रूप से भी बना। अलगाववाद की जड़ें काट दी गईं। वह कानून जो पुरुष की तीन बोलियों पर एक मुस्लिम महिला का जीवन बर्बाद कर देता था, मोदी सरकार ने उस ट्रिपल तलाक को समाप्त किया। यही असली महिला सशक्तिकरण है। आयुष्मान भारत ने 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ माताओं के चूल्हे गैस से जले। जल जीवन मिशन ने भारत के 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया। पी.एम. आवास योजना से करोड़ों परिवारों को पक्की छत मिली। पी.एम. किसान सम्मान निधि से किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंचे। 80 करोड़ भारतीयों को भोजन, यह है अंत्योदय का व्यावहारिक स्वरूप।

पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति के लिए मेडिकल कैंप, जशपुर में राज्यपाल रमेन डेका ने दिए निर्देश

जशपुर। गवर्नर रमेन डेका रविवार को सीएम के गृह जिले जशपुर दौरे पर रहे। राज्यपाल ने अपने दौरे के दौरान जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और जनजातीय विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश दिए, वहीं पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण पर्यटन, महिला सशक्तिकरण और धार्मिक आस्था से जुड़े कार्यक्रमों में भी शामिल हुए।

जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्यपाल डेका ने विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा और बिरहोर परिवारों के लिए हर महीने मेडिकल कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा, इन समुदायों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के साथ उनकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाना जरूरी है। संभावित टीबी मरीजों की पहचान, सिकल सेल बीमारी की रोकथाम तथा महिलाओं में स्तन कैंसर की जांच और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने पर भी राज्यपाल ने जोर दिया। रमेन डेका ने गंभीर मरीजों को रायपुर, अंबिकापुर और एम्स जैसे संस्थानों में रेफर करने के निर्देश भी दिए।

राज्यपाल ने रेड क्रॉस सोसायटी को गांव-गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें असम और ओडिशा भेजकर हस्तशिल्प और नए डिजाइन सीखने की पहल को बढ़ावा देने की बात कही। जशपुर की लखपति दीदी लालमणि प्रजापति के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें राजभवन में सम्मानित करने की घोषणा की।

पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्यपाल ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। इसी कड़ी में उन्होंने सर्किट हाउस स्थित मातृत्व वन में सीता अशोक का पौधा लगाया। लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस वन में 400 से अधिक प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ सामाजिक संवेदनाओं का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि पहल आने वाली पीढ़ियों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और मातृत्व के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करेगी।

कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए राज्यपाल ने किसानों को जैविक खेती, वर्मी कम्पोस्ट और आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। जल संरक्षण के तहत डबरी निर्माण, पुराने कुओं के जीर्णोद्धार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अमृत सरोवर और सोकपिट निर्माण जैसे कार्यों को गति देने पर जोर दिया गया। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने और योग को बढ़ावा देने की बात कही।

राज्यपाल डेका ने देशदेखा के समीप केरेगांव में विकसित होम-स्टे का भ्रमण कर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने वाली पहल की सराहना की। उन्होंने स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार पारंपरिक व्यंजनों जैसे महुआ रोटी, चीला और पीठा का स्वाद चखा और 'जसक्राफ्ट' ब्रांड के तहत बनाए जा रहे हस्तशिल्प उत्पादों की प्रशंसा की। राज्यपाल ने कहा कि यह प्रयास न केवल स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करते हैं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाते हैं।

कभी नक्सलियों की दहशत में जीता था 35 घरों का गांव, आज उसी गांव का गरीब बेटा बना एसआई

बालोद। बालोद जिले के अंतिम छोर पर बसे आदिवासी विकासखंड डौंडी के 35 घरों की आबादी वाले ग्राम पेवारी का लाल ललित गावड़े जब (एसआई) स्ट्रु की ट्रेनिंग पूरी कर घर लौटा, तो पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। ललित की इस उपलब्धि से गांव ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी लोग उसे बधाई देने उसके घर पहुंचने लगे। इस गांव के कुछ साल पहले नक्सलियों की मौजूदगी से गांव के लोग थर-थर कांपते थे।

इस गांव में नक्सलियों ने बम भी प्लांट किया था, जिसे फोर्स की मदद से डिफ्यूज किया गया था। नक्सलियों की दहशत के बीच गांव के युवा रहने को मजबूर थे। आज नक्सल खात्मे के साथ-साथ युवा अपने करियर की तरफ ध्यान देने लगे हैं और बड़ा मुकाम हासिल करने लगे हैं, जिसका जीता-जागता उदाहरण ललित गावड़े बन गया है।

ललित गावड़े बहुत गरीब परिवार से आते हैं। माता-पिता ने मजदूरी कर ललित को पढ़ाया। ललित की तीन बहनें और एक भाई हैं। ललित चौथे नंबर का है। गांव में प्राथमिक तक पढ़ाई की। उसके बाद हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी तक कांकेर जिले में पढ़ाई की। जिसके बाद ललित रायपुर चले गए। आगे की पढ़ाई रायपुर में करते रहे।

मजदूर माता-पिता ललित के लिए दिन-रात मजदूरी करते रहे और उसे पैसे भेजते रहे, ताकि उनका बेटा अफसर बन सके। आज उसकी उपलब्धि से माता-पिता समेत पूरा गांव खुशियों से झूम रहा है। एसआई ललित की माता रुपई बाई कहती हैं कि उनके बेटे की उपलब्धि से वे काफी खुश हैं।

मेरे बेटे ने गांव के साथ-साथ पूरे जिले का नाम गौरवान्वित किया है। हम काफी गरीबी में जीकर बेटे की हर चीज पूरी करते थे।

गांव के हर बेटा-बेटी को पढ़ाई कर मुकाम हासिल करना चाहिए। ललित के छोटा भाई अमर सिंह गावड़े भी भाई की तरह एसआई बनना चाहता हैं। अमर ने भी एसआई के लिए फिजिकल परीक्षा पास कर ली है और आगे की तैयारी कर रहे हैं। उनका सपना है कि अपने भाई की तरह ही वह भी अफसर बने और देश की सेवा करें।

जनपद पंचायत अध्यक्ष डौंडी मुकेश कौड़ो द्वारा बताया गया कि इस बेटे ने गरीबी में पढ़ाई कर हमारे गांव के साथ-साथ पूरे जिले का नाम रोशन किया है। हमारा पूरा गांव इस बेटे की उपलब्धि से खुश है।

ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग

बलौदाबाजार। जिले के कटगी में एक बड़ी आगजनी की घटना हुई है। यहां स्थित रमेश ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि करीब 3 घंटे तक धधकती रही। इस भीषण आग में दुकान में रखे ऑटो पार्ट्स के लाखों रुपये के सामान के साथ-साथ दूसरे कमरे में रखी नगदी रकम भी जलकर पूरी तरह राख हो गई। वहीं आग पर काबू पाने के लिए, आसपास के लोग व फायर ब्रिगेड की टीम जुटी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना की सूचना मिलते ही कसडोल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इस आगजनी की घटना में करीब 10 से 15 लाख रुपये से अधिक के नुकसान हुआ है। फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

नहर में दरार: बैकुंठपुर के ग्राम पंचायत भांडी में बना नया कनाल

कोरिया। किसानों के खेतों तक नहर के जरिए पानी पहुंचाने की बड़ी योजना सरकार ने बनाई है। योजना के तहत ग्राम पंचायत भांडी में जल संसाधन विभाग ने नहर का निर्माण भी कराया। निर्माण कार्य पूरा हुए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं बीता था कि उससे पहले नहर में कुछ जगहों पर दरारें साफ नजर आने लगी है। ग्राम भांडी के लोग अब दरारों को लेकर परेशान होने लगे हैं। ग्राम पंचायत भांडी की जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से दूरी मात्र 2 किमी की है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लाखों की लागत से बने इस निर्माण में अभी से दरारों का आना ठीक संकेत नहीं है। गांव वालों का कहना है कि घटिया मेटेरियल का इस्तेमाल करने से ये दिक्कतें आई हैं।

गांव वालों ने कहा कि कई जगहों पर पैच वर्क भी किया गया है जो ये बताता है कि लापरवाही को ढकने की कोशिश हुई है। ग्रामीण चाहते हैं को अगर कहीं निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है तो उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। नहर में कई जगहों पर आई दरारों और निर्माण कार्य में लापरवाही बरते जाने को लेकर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता ने कहा, जो जी दिक्कतें जहां कहीं भी आई हैं वहां दूर की जाएंगी। अभियंता ने कहा कि एक दो जगह क्रैक आया होगा, उसे हम जल्द ही सुधरवा देंगे। अभियंता ने ये माना कि हर निर्माण कार्य में कुछ कमियां होती हैं, जिन्हे समय-समय पर ठीक किया जाता है। विभाग की ओर से दी गई इस दलील पर गांव वाले खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्य के पूरा हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। ऐसे में दरारें आना कई गंभीर विषयों की ओर इशारा करता है।

गिरते भू-जल स्तर पर सख्ती 30 जून तक नलकूप खनन पर रोक

बिलासपुर। जिले में गिरते भू-जल स्तर और संभावित पेयजल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए नए नलकूप एवं ट्यूबवेल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 6 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय अग्रवाल द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में नए नलकूप/ट्यूबवेल खनन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि भू-जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। इस स्थिति को नियंत्रित करने तथा पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-3 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

आदेश के तहत बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर एवं कोटा को 6 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संस्था नए नलकूप खनन नहीं कर सकेगी। हालांकि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगर निगम एवं नगर पंचायतों जैसी शासकीय एजेंसियों को केवल पेयजल आपूर्ति हेतु आवश्यकता अनुसार नलकूप खनन की अनुमति दी गई है। इसके लिए उन्हें पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन संबंधित कार्यों की जानकारी अधिकृत अधिकारियों को देना अनिवार्य होगा।

जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में नलकूप खनन की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर, बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर एवं कोटा को अधिकृत किया गया है। ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अनुमति देने की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

सरपंच की पिटाई से अस्पताल के कर्मचारी की मौत

कोरबा। कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मॉर्चरी में शव पोस्टमार्टम के लिए लाए जाने पर सरपंच जयवीर सिंह ठाकुर ने इंतजार करने को कहा तो तैश में आकर बुजुर्ग कर्मचारी बालकृष्ण चनईया को बुरी तरह पीटा और सिर दीवार पर पटक दिया। गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कर्मचारी की सोमवार सुबह मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शवगृह में बुजुर्ग कर्मचारी से मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया था। इस घटना में गंभीर रूप से घायल कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी सरपंच पर तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। मार्च 30, 2026 को एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हुई थी। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह लाया गया। वहां पहुंचे सरपंच जयवीर सिंह ठाकुर ने कर्मचारियों से जल्दी पोस्टमार्टम करने की जिद की।

काम में व्यस्त बुजुर्ग कर्मचारी बाल कृष्ण चनैया ने इंतजार करने को कहा। इससे तैश में आकर सरपंच ने उसकी पिटाई कर दी। उसने बुजुर्ग कर्मचारी का सिर दीवार में भी पटक दिया था। गंभीर रूप से घायल कर्मचारी गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती था। सोमवार को सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक बाल कृष्ण चनैया की बड़ी बेटी लक्ष्मी ने बताया कि पिता के साथ ड्यूटी के दौरान मारपीट हुई है। इसी के चलते उनकी मौत हुई है। उन्होंने आरोपी सरपंच बेंद्रकोना निवासी जयवीर सिंह ठाकुर की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। इस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी पोस्टमार्टम करने से मना कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

युवक को नग्न कर बीच सड़क लात-घूंसों से पीटा

कोरबा। कोरबा में युवक ने शराब पीने के लिए दोस्त की बाइक बेच दी। इसके बाद उसकी नग्न कर सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पिटाई की गई। अब मारपीट का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला 27 मार्च है, लेकिन वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर आरोपी दोस्त के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उसकी तलाश में जुट गई है। घटना दर्री थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक का नाम अमरदास (36) है, जो शराब पीने का आदी है। वह कावेरी विहार के सर्वेंट क्वार्टर में रहता है, जबकि पत्नी अधिकारियों के घरों में साफ-सफाई का काम करती है। बताया जा रहा है कि 27 मार्च को अमरदास अपने दोस्त सरोज कुमार के पास पहुंचा और उसकी बाइक लेकर शराब पीने चला गया। बाद में जब अमरदास वापस लौटा, तो उसके पास बाइक नहीं थी। पता चला कि वह शराब के लिए बाइक बेच दी है। इसके बाद दोस्त ने उसकी जमकर पिटाई की, उसे कपड़े उतारकर नग्न कर दिया गया और सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा।

बेलतरा में 30 साल बाद बन रही सड़क, जताया आभार

बिलासपुर। बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 30 साल बाद सड़क निर्माण हो रहा है। यहां सड़क नहीं बनने से परेशान लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी थी। विधायक सुशांत शुक्ला की पहल पर अलग-अलग गांवों में कुल 14 करोड़ 56 लाख 34 हजार रुपए की लागत से सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलापूजन किया। लोगों के लंबे इंतजार के बाद अब उन्हें आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल, बेलतरा क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं, जो आज भी पहुंच विहीन हैं, यहां डब्ल्यूबीएम और कच्ची सड़क है, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में आसपास के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां लंबे समय से जर्जर सड़कों के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा था। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जब वो चुनाव के समय इन गांवों में पहुंचे थे, तब लोगों की केवल एक ही मांग थी सड़क निर्माण। इसे लेकर उन्होंने चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी थी।

रायगढ़ में डीजीपी ने जिले की पुलिसिंग को सराहा

रायगढ़। रायगढ़ जिला में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सड़क मार्ग से जशपुर से रायगढ़ पहुंचे। जहां उन्होंने सोमवार की सुबह होमगार्ड में फायर यूनिट का निरीक्षण किया। फायर ब्रिगेड वाहनों के प्रदर्शन के बाद उनकी जानकारी ली। साथ ही डीजीपी ने जिले की पुलिसिंग की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान समय में पुलिसिंग का मूल मंत्र समाज के साथ विश्वास स्थापित कर क्राईम कंट्रोल करना है, जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस प्रभावी रूप से निभा रही है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के दो फायर ब्रिगेड वाहन वर्तमान में रायगढ़ फायर स्टेशन में संचालित हैं, जिस पर डीजीपी अरुण देव गौतम ने कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी से चर्चा कर उन वाहनों को शीघ्र सारंगढ़ भेजने और वहां फायरमैन की उपलब्धता पर चर्चा किया गया। इसके बाद डीजीपी ने छठवीं वाहिनी का निरीक्षण कर परिसर की साफ-सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने बताया कि वे सरगुजा रेंज के दौरे के दौरान जशपुर से रायगढ़ पहुंचे हैं।

दो पक्षों में विवाद सांप्रदायिक तनाव, पुलिस बल तैनात

सरगुजा। जिले के डूमरडीह में वाहनों की मामूली टक्कर के बाद शुरू हुए विवाद ने सांप्रदायिक तनाव का स्वरूप ले लिया। फार्म हाउस में घुसकर हिंदू युवक के साथ मारपीट के बाद मुस्लिम समुदाय के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इधर हिंदू समाज के लोगों ने डूमरडीह में रैली निकाल आटो और गुमटी को आग के हवाले कर दिया। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। मामला धौरपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, विवाद की शुरुआत दो अप्रैल को हुई। धौरपुर निवासी रोहितेश्वर प्रताप सिंह अपने घर से ककनी स्थित अपने फार्म हाउस जा रहे थे। रास्ते में नाले के पास डूमरडीह निवासी कादिर खान की आटो से कार की मामूली टक्कर हो गई। घटना के बाद कादिर खान फार्म हाउस पहुंचा और रोहितेश्वर से गाली गलौज कर वापस लौट गया। फार्म हाउस में विवाद के बाद रोहितेश्वर प्रताप सिंह ग्राम रवई होकर वापस डूमरडीह हाईस्कूल के पास पहुंचा, तभी कादिर खान ने उसकी कार को रोक लिया। मौके पर कुछ और लोग पहुंच गए।

पैसा-डबल करने का झांसा देकर 10 लाख ठगे

दुर्ग-भिलाई। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में रकम दोगुना करने और लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने अलग-अलग लोगों को लालच देकर 10 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार, 5 अप्रैल को पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में दर्ज दो धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई की गई। जांच के दौरान रायपुर नाका निवासी लक्ष्मी टांडी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला लोगों को कम समय में रकम दोगुना करने और आसान तरीके से लोन दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठती थी। पहले मामले में सारपल्ली भास्कर नाम के व्यक्ति को 6 महीने में रकम दोगुनी करने का लालच दिया गया। आरोपी ने उनसे करीब 3 लाख रुपए नगद लिए और 7 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए। पैसे लेने के बाद महिला ने रकम वापस नहीं की।

हथियारबंद नक्सली छत्तीसगढ़ से हुए खत्म

बंगाल से ममता दीदी की विदाई इस बार तय : विजय शर्मा

कबीरधाम। नक्सलवाद के खात्मे के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री विजय शर्मा पहली बार कवर्धा पहुंचे। कवर्धा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए विजय शर्मा ने कहा, अब छत्तीसगढ़ के ट्राई जंक्शन वाले इलाके में कुछ गिने चुने नक्सली बचे हैं। जो बचे हुए माओवादी हैं वो बिना हथियार और वर्दी वाले हैं। जल्द उनको भी समाज की मुख्यधारा में लाकर इस समस्या का समूल नाश कर दिया जाएगा। विजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनता से वादा किया था। दोनों ने कहा था कि हम तय समय सीमा के भीतर नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। विजय शर्मा ने कहा कि जनता से अपना वादा पूरा किया। शासन की योजनाओं का भी हमें लाभ मिला। बड़ी संख्या में माओवादियों ने हथियार डालकर माज की मुख्यधारा में शामिल होने का बड़ा फैसला लिया गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो रणनीति बनाई गई, उसका पूरा-पूरा श्रेय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को जाता है। विजय शर्मा ने कहा कि जो लक्ष्य हमने 31 मार्च 2026 को हासिल किया उस लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ा योगदान, हमारे जवानों का रहा है। विजय शर्मा ने कहा कि हमारे जवान इस सफलता और श्रेय के असली हकदार हैं।अपने कवर्धा दौरे पर विजय शर्मा ने नगर के प्रमुख मंदिरों और गुरुद्वारे में माथा टेककर प्रभु का आशीर्वाद लिया। इसके बाद भारत माता चौक में आयोजित स्वागत समारोह में समाज प्रमुखों ने विजय शर्मा को शॉल, श्रीफल देकर सम्मानित किया। सामाजिक संगठनों की ओर से विजय शर्मा को मोतीचूर के लड्डुओं से तौला भी गया।

कोरिया में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, शिवपुर चरचा में धूल फांक रही एंबुलेंस

कोरिया। नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। विधायक निधि से जनता की सुविधा के लिए उपलब्ध कराई गई एंबुलेंस प्रशासनिक लापरवाही के चलते सालों से खराब होकर खड़ी है। लगभग 35 से 40 हजार की आबादी वाले इस नगर में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का यह महत्वपूर्ण साधन आज पूरी तरह ठप पड़ा है।

शिकायत है कि बंद पड़ी एंबुलेंस लंबे समय तक बिना पंजीयन के ही संचालित होती रही, जो नियमों के खिलाफ है। वर्तमान में पंजीयन के अभाव में इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को जिला अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिसका खर्च हर किसी के बस की बात नहीं है। पूर्व पार्षद रामाधार टोप्पो ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के एंबुलेंस का संचालन कानून के साथ सीधा खिलवाड़ है।

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि पूर्व विधायक अंबिका सिंहदेव द्वारा जनता की सुविधा के लिए यह एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन नगर पालिका की उदासीनता ने इसे कबाड़ में तब्दील कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि एंबुलेंस के पंजीयन के लिए आरटीओ में केवल एक साधारण आवेदन देना होता है और इसमें किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगता, फिर भी अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होना गंभीर लापरवाही है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी वी.के. ओझा का बयान इस मामले में और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस पिछले शासनकाल में खरीदी गई थी, लेकिन उससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है। उन्होंने बताया कि फिलहाल वाहन खड़ा है और आवश्यक कागजात मिलने के बाद ही इसे चालू किया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका ने श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट को सौंपी एम्बुलेंस की चाबी

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने सोमवार

को गायत्री नगर रायपुर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में मंदिर ट्रस्ट को एम्बुलेंस प्रदान किए। उन्होंने अपने स्वेच्छानुदान मद से प्रदत्त 6 लाख 80 हजार की लागत के एम्बुलेंस की चाबी सौंपी और हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। इस वाहन का उपयोग श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट में किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा सहित ट्रस्ट के पदाधिकारी उपस्थित थे।

लोकभवन में लगा होम्योपैथिक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका की पहल

पर सोमवार को लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में होम्योपैथिक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 60 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों तथा उनके परिजनों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इसका लाभ उठाया। शिविर में चिकित्सकों ने रक्तचाप, मधुमेह, आर्थराइटिस, रक्त संबंधी समस्याएं, सनस्ट्रोक, चिकनपॉक्स सहित विभिन्न बीमारियों के लिए होम्योपैथिक दवाइयां निःशुल्क प्रदान की गई। चिकित्सकों ने उपस्थित लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिया गया। राज्यपाल श्री डेका स्वयं शिविर में पहुंचकर अपने रक्तचाप (बी.पी.) एवं वजन की जांच कराई। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने कहा कि समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने से बीमारियों की समय रहते पहचान संभव होती है और बेहतर उपचार किया जा सकता है। इस स्वास्थ्य शिविर में रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के चिकित्सकों और स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

नल पर पानी लेने गए झारखंड के कारपेंटर पर गिरी मिट्टी, अस्पताल में तोड़ा दम

रायपुर। कचना क्षेत्र स्थित रहेजा सोसाइटी में काम करने वाले एक कारपेंटर की ऊपरी हिस्से से मिट्टी गिरने के कारण मलबे में दबकर उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान झारखंड निवासी गुड्डू रवि के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामला की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, गुड्डू रवि सोसाइटी के भीतर कारपेंटर का काम कर रहा था। काम के दौरान वह पास ही स्थित एक नल पर पानी लेने के लिए गया था। इसी दौरान नल के ऊपर स्थित मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया और गुड्डू उसकी चपेट में आ गया। मलबे के नीचे दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उसे बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही खम्हारडीह थाना पुलिस मौके पर पहुँची। मृतक झारखंड का रहने वाला था, जिसके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

बिजली बिल से राहत, छत्तीसगढ़ सरकार की समाधान योजना बनी मददगार

रायपुर। बढ़ते बिजली बिल और सरचार्ज से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। यह योजना

महज छूट तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक बोझ से दबे परिवारों को आत्मविश्वास और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। योजना के तहत उपभोक्ताओं की मूल बकाया राशि में 50 से 75 प्रतिशत तक की छूट और सरचार्ज में 100 प्रतिशत माफी मिल रही है। साथ ही, केवल 10 प्रतिशत राशि जमा कर शेष भुगतान आसान किस्तों में करने की सुविधा इसे और भी सुलभ बनाती है। मोर बिजली ऐप और नजदीकी वितरण केंद्रों के माध्यम से पंजीयन प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। मनेन्द्रगढ़ की शाहीन बेगम इसकी जीवंत मिसाल हैं। करीब 48 हजार रुपये के बकाया में 23 हजार रुपये से अधिक की छूट मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में लगभग 28 लाख उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने वाली इस योजना के तहत करीब 757 करोड़ रुपये की राहत दी जा रही है। यह पहल सरकार और नागरिकों के बीच भरोसे की नई नींव भी मजबूत कर रही है।

जग्गी हत्याकांड: अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा

बिलासपुर। 2003 के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की अपील स्वीकार कर ली। इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बरी करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया गया।

अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्हें आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त छह माह के सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी। हाईकोर्ट का यह निर्णय 31 मई 2007 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट देता है।

उस समय स्पेशल जज रायपुर ने अमित जोगी को बरी कर दिया था। हालांकि, चिमन सिंह, याह्या ढेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी सहित अन्य 28 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही गवाही पर कुछ आरोपियों को दोषी ठहराना और मुख्य

साजिशकर्ता को बरी करना कानूनी रूप से असंगत और गलत है। यह फैसला 2003 के चर्चित हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले को दोबारा खोला गया था। इसके बाद ही हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपना निर्णय दिया।

यह फैसला न्याय प्रणाली में समानता और निष्पक्षता के महत्व को दर्शाता है। अदालत ने एक ही साक्ष्य के आधार पर अलग-अलग निर्णय को असंगत बताया। इस निर्णय से 2003 के चर्चित हत्याकांड में न्याय की उम्मीदें बढ़ी हैं। अमित जोगी को अब आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी।

बता दें, कि पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी 2003 के राम अवतार जग्गी हत्याकांड में सजा सुनाई गई है। साल 2007 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन सीबीआई और शिकायतकर्ता ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। नवंबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की अपील को तकनीकी आधार पर खारिज करने के बाद पुनः बहाल कर दिया था।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बड़ा झटका लगा है। जग्गी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अमित जोगी को तीन सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। यह फैसला हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनाया है। अदालत के आदेश के मुताबिक जोगी को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा। विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर अमित जोगी पर भी चार्ज भी लगाए गए थे और आज अंतिम सुनवाई के बाद उन्हें दोषी माना गया है। अब उन्हें तीन हफ्ते के अंदर में सरेंडर करना होगा।

प्रदेश में वर्ष 2003 में हुए बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने अमित जोगी को दोषी करार दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने उन्हें तीन हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की स्पेशल डिवीजन बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया है। इससे पहले कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में रीओपन किया गया। मामले की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई ने कोर्ट में 11 हजार पन्नों की रिपोर्ट पेश की थी। इसी विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर अमित जोगी पर भी चार्ज लगाए गए थे और आज अंतिम सुनवाई के बाद उन्हें दोषी माना गया है। अब उन्हें तीन हफ्ते के अंदर में सरेंडर करना होगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मामले की सुनवाई के दौरान स्व राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता की हत्या एक राजनीतिक साजिश थी। सीबीआई ने 11 हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की थी, जिसमें हत्या से जुड़े पर्याप्त सबूत शामिल हैं।

न्यायपालिका का यह फैसला सराहनीय : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाईकोर्ट के द्वारा अमित जोगी को आजीवन कारावास का फैसला सुनाने का स्वागत करते हुए कहा कि न्यायपालिका का यह फैसला सराहनीय है और देर आए, दुरुस्त आए की कहावत को चरितार्थ करता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अमित जोगी को मुख्य आरोपी माना गया है और अब न्याय की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने से राहत की भावना देखी जा रही है।

अमित जोगी को उम्रकैद के फैसले का सतीश जग्गी ने किया स्वागत

रायपुर। चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इसे न्याय की जीत कहा है। 23 वर्षों के बाद परिवार को न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि इन 23 वर्षों में हमें राजनीतिक शक्तियों के साथ मनी पॉवर से भी लड़ना पड़ा। सतीश जग्गी ने मांग की है कि अमित जोगी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उनका पासपोर्ट भी जब्त होना चाहिए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा स्थापना दिवस पर किया ध्वजारोहण

■ कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं, अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करने का लिया संकल्प

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विधिवत ध्वजारोहण किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री साय ने भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा और संगठन की ताकत ही उसे लगातार आगे बढ़ा रही है। इस मौके पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर हमेशा बना रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस कल्पना और दृष्टि के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था, उनकी सरकार उसी दिशा में काम करते हुए उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करेगी।

वहीं पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हाल ही में वे वहां से होकर आए हैं और प्रदेश में ममता बैनर्जी के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और बहन-बेटियों को भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के पक्ष में अच्छा माहौल बन चुका है और वहां परिवर्तन की लहर चल रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी।

एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने निकली छत्तीसगढ़ की बेटी, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जांजगीर-चांपा जिले की युवा पर्वतारोही सुश्री अमिता श्रीवास को उनके आगामी माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में पर्वतारोही सुश्री अमिता श्रीवास से मुलाकात के दौरान कहा कि आगामी 9 अप्रैल को सुश्री अमिता विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के संकल्प के साथ काठमांडू के लिए रवाना हो रही हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि की यात्रा नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं, साहस और आत्मविश्वास की ऊंची उड़ान है।

उन्होंने कहा कि अमिता का यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि यदि संकल्प अटल हो, तो कोई भी ऊंचाई असंभव नहीं रहती। प्रदेश की

बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से नए मानक स्थापित कर रही हैं और छत्तीसगढ़ को नई पहचान दे रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अमिता श्रीवास ने वर्ष 2021 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माउंट किलिमंजारो को फतह कर पहले ही अपनी क्षमता और दृढ़ता का परिचय दिया है। उनका यह सतत प्रयास न केवल उपलब्धि है, बल्कि प्रदेश की युवा पीढ़ी, विशेषकर बेटियों के लिए एक जीवंत प्रेरणा है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अमिता अपने इस साहसिक अभियान में सफलता प्राप्त कर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर देश का तिरंगा फहराएंगी और छत्तीसगढ़ सहित पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगी।

मुख्यमंत्री ने सुश्री अमिता श्रीवास को इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

पवन कुमार ने हिंसा का रास्ता छोड़ जीवन की नई शुरुआत की

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सुशासन सरकार की सरकार ने माओवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 हिंसा छोड़ मुख्यधारा से जुड़ने वाले नक्सलियों को नई जिंदगी दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादी आत्मसमर्पितों को 5 लाख तक की सहायता, कौशल प्रशिक्षण, और सम्मानजनक जीवन प्रदान कर नक्सल-मुक्त बस्तर के सपने को साकार कर रही है। कोण्डागांव जिले के फरसगांव के सुदेर पंचायत चिंगनार के श्री पवन कुमार को पुनर्वास नीति के तहत पक्का आवास मिलने से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

कोण्डागांव जिले के विकासखण्ड फरसगांव के दूरस्थ ग्राम पंचायत चिंगनार, जो मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, कभी

इस क्षेत्र में माओवाद के प्रभाव के कारण भय और असुरक्षा का माहौल था। अब इन क्षेत्रों में राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत शांति और विकास स्थापित हो रहा है। इसी गांव में रहने वाले श्री पवन कुमार को पुनर्वास नीति के तहत पक्का आवास मिलने से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। पवन कुमार पूर्व में माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे। उस दौर में उनका जीवन असुरक्षित और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार जंगल किनारे एक झोपड़ी और जर्जर कच्चे मकान में रहने को मजबूर था, जहां न तो पर्याप्त सुविधाएं थीं और न ही सुरक्षित भविष्य की कोई उम्मीद। समय के साथ उन्होंने यह महसूस किया कि हिंसा का मार्ग केवल विनाश की ओर ले जाता है। शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर उन्होंने साहसिक निर्णय लेते हुए माओवादी संगठन से नाता तोड़ लिया और समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आत्मसमर्पण के बाद जिला प्रशासन द्वारा विशेष परियोजना आवास (आत्मसमर्पित परिवार) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में उन्हें आवास स्वीकृत किया गया।

छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग

एनएसयूआई ने किया तीन विश्वविद्यालयों का घेराव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में छात्रसंघ चुनाव फिर से शुरू करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज सड़कों पर उतरे और तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और आयुष विश्वविद्यालय का घेराव करते हुए छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग उठाई।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रदर्शन सबसे ज्यादा उग्र रहा, जहां बड़ी संख्या में छात्र जुटे और जमकर नारेबाजी

की। एनएसयूआई के प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल ने कहा कि उनकी एकमात्र मांग है कि प्रदेश में पिछले कई वर्षों से बंद छात्रसंघ चुनाव को फिर से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि छात्रहितों की आवाज बुलंद करने के लिए छात्रसंघ चुनाव बेहद जरूरी है। प्रदर्शन के चलते विश्वविद्यालय परिसरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस जवानों के बीच झूमाझटकी भी हुई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, छात्रों का आंदोलन जारी है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि अगर मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। प्रदर्शन में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, शांतनु झा, प्रशांत गोस्वामी, पुनेश लहरे, संकल्प मिश्रा सहित हजारों की संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्ति पर उप मुख्यमंत्री शर्मा का हुआ भव्य अभिनंदन

■ यह जीत जनभागीदारी, सुरक्षा बलों के साहस और बस्तरवासियों के विश्वास की जीत : विजय शर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सहित देश के लिए ऐतिहासिक क्षण तब आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च को सदन में शस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति की घोषणा की। लगभग चार दशकों से इस समस्या से जूझ रहे छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा के दृढ़ संकल्प, रणनीति और सतत प्रयासों से यह बड़ी सफलता हासिल की।

इस अभियान में भारतीय सेना, पुलिस और समस्त सशस्त्र बलों के जवानों के अदम्य साहस, समाज की जागरूक भागीदारी, राजनीतिक नेतृत्व की इच्छाशक्ति, पत्रकार बंधुओं की भूमिका और सबसे बढ़कर बस्तर के नागरिकों के सहयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभी के समुचित प्रयासों से ही सशस्त्र नक्सलवाद का अंत संभव हो सका और अब बस्तर में खुशहाली की नई शुरुआत हो रही है।

सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ बनने के बाद उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र कवर्धा पहली बार पहुंचे। जहां पर स्थानीय महामाया चौक में कवर्धा के लोगों ने उनके लिए भव्य ऐतिहासिक नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया। जिसमें हजारों की संख्या में लोग बाजा-गाजा, ढोल-नगाड़ों के साथ शामिल हुए, पूरे शहर में जश्न का वातावरण नजर आया। सभी को गर्व था कि कभी नक्सल प्रभावित कबीरधाम जिले के साथ अब पूरे छत्तीसगढ़ से भय और आतंक को दूर करने में उनके अपने माटी पुत्र का बड़ा योगदान रहा है।

इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज, यादव समाज, ठाकुर समाज, कुर्मी समाज, साहू समाज, सतनामी समाज, निर्मलकर समाज, गुप्ता समाज, अहिरवार समाज, लोधी समाज, पटेल समाज, गोंड समाज, केसरवानी गुप्ता समाज, सेन समाज, गंधर्व समाज, स्वर्णकार समाज, जैन समाज, वैष्णव समाज सहित सभी समाजों ने भव्य रैली का स्वागत कर इस असंभव से लगने वाले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। जहां स्थानीय जिला प्रेस क्लब, यूथ क्लब, हरीतिमा परिवार, प्राइवेट स्कूल संघ, नाथ योगी समाज, फाइटर क्लब, जिला क्रिकेट संघ, ज्वाइन हैंड रुप, ट्रक मालिक संघ, पतंजलि योग समिति, सीनियर सिटीजन समिति एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व

कार्यकर्ताओं ने भी शामिल होकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर सभी ने गृह मंत्री श्री विजय शर्मा को लड्डुओं से तौलकर उनका सम्मान किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गायत्री मंदिर और गुरुद्वारे में जाकर प्रदेश की शांति और समृद्धि की प्रार्थना की और लोगों के साथ भारतमाता चौक पर नक्सल अभियान में शहीद हुए अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी के प्रेम से अभिभूत हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप सब नक्सल समस्या को इतनी गंभीरता से समझते हैं। यह वास्तव में अत्यंत संवेदनशील विषय रहा है, और जो लोग इससे पीड़ित रहे हैं, उनकी पीड़ा को शब्दों में समझा भी नहीं जा सकता। माओवाद एक आयातित विचार है, जिसका उद्देश्य केवल बंदूक की नली से सत्ता स्थापित करना रहा है, जबकि भारत का लोकतंत्र प्राचीन काल से ही सशक्त रहा है, जिसकी झलक आज भी बस्तर के समाज में दिखाई देती है।

उन्होंने नक्सल हिंसा की भयावहता का उल्लेख करते हुए कहा कि भोले-भाले लोगों को बहलाकर उनके हाथों में बंदूक थमा दी गई। स्कूल, सड़क और तालाबों के किनारे बारूद बिछाए गए। शिक्षा दूत, सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, शासकीय कर्मचारी और निर्दोष ग्रामीणों तक की निर्मम हत्या की गई। सैकड़ों लोग इन विस्फोटों में अपंग हो गए, उनके मानवाधिकारों की रक्षा कौन करेगा? जब बस्तर के ऐसे पीड़ितों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया जाएगा और जब गृह मंत्री संकल्प लेते हैं, तो वह तय समय में पूरा होता है।

उन्होंने कहा कि यह सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं है, इसमें सेना, पुलिस और सभी सुरक्षा बलों के जवानों का साहस, समाज का सहयोग, राजनीतिक नेतृत्व की इच्छाशक्ति, पत्रकार बंधुओं का योगदान और सबसे बड़ा श्रेय बस्तर के नागरिकों को जाता है। सभी के सामूहिक प्रयास से ही यह संभव हो पाया है। यह जीत जनभागीदारी, सुरक्षा बलों के साहस और बस्तरवासियों के विश्वास की जीत है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने शस्त्र छोड़ने वालों के लिए लाल कारपेट बिछाकर स्वागत किया और उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की। हमने संवाद के लिए वीडियो कॉल तक को माध्यम बनाया। उन्होंने आगे कहा कि आज बस्तर के गांवों में लोग अपने आंगन में खुलकर हंस रहे हैं। अब वहां डर नहीं, विकास की बातें हो रही हैं। गांवों के मेले और बाजारों में रौनक लौट आई है, यह बदलाव ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में दशकों से लंबित कई बड़े निर्णय जैसे राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 निर्धारित समय में पूरे हुए। उसी श्रृंखला में नक्सल समस्या का समाधान भी संभव हुआ है। उन्होंने इस भव्य सम्मान के लिए कवर्धा के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त किया।

बंगाल चुनाव में कांग्रेस खोल सकती है खाता!

सत्येंद्र प्रताप सिंह

49 साल पहले 1977 में बंगाल की सत्ता से कांग्रेस बेदखल हुई थी। इसके बाद हुए प्रत्येक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का आंकड़ा कभी भी तीन अंकों वाली संख्या को छू नही पाया। सत्ता से जब बेदखल हुई थी तो 20 सीटें आई थीं। जबकि सत्ता में 200 से अधिक सीटों पर जीत कर आई थी। विधानसभा चुनाव 1982 में इसके बाद 49 सीटें, 1987 में 40 सीटें, 1991 में 43 सीटें, 1996 में 82 सीटें, 2001 में 26 सीटें, 2006 में 21 सीटें, 2011 में 42 सीटें, 2016 में 44 सीटें और 2021 में खाता तक नहीं खुला था। गौरतलब है कि सिर्फ एक बार 1996 में 50 का आंकड़ा पार हुआ था। 2026 विधानसभा चुनाव, कांग्रेस अपने बलबूते अकेले 294 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में लोकसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार और संसद के दोनों सदनों की पूर्व सदस्य मौसम नूर के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह व ऊर्जा आ गई है। कांग्रेस ने उम्मीदवार भी बहुत सोच समझकर उतारा है। अधीर रंजन चौधरी को उनके परंपरागत गढ़ बहरमपुर से टिकट दिया गया है, जो करीब 30 साल के बाद विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। आखिरी बार 1996 में नवग्राम सीट से विधानसभा चुनाव लड़े व जीते थे। दूसरा प्रमुख नाम मौसम नूर का है, जिन्होंने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से वापसी की हैं। मालदा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मौसम नूर को मालतीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने किसी भी गैर राजनीतिक सेलेब्रिटी को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। इस बार राज्य में अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए अपने पुराने वफादारों पर ही भरोसा कायम रखा है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों में 68 दलित तो 64 मुस्लिम उतारे हैं। इसके अलावा 16 अनुसूचित जनजाति से हैं तो 42 महिला उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने दलित और मुस्लिम पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है, जो ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के लिए सियासी टेंशन बन सकता है। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर विशेष ध्यान दिया है तो मुस्लिम बहुल जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में पार्टी ने अपने मजबूत संगठनात्मक ढांचे के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया है, जिससे त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। आज कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है। आखिर यह स्थिति क्यों आई? यह जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल, 1977 से 1998 तक 21 वर्षों की लगातार हार के बाद सब्र का बांध टूटना ही था। वैसे भी कांग्रेस की राजनीति में सबसे अधिक असहज ममता बनर्जी महसूस कर रही थीं। लिहाज़ा इसी साल ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बना लीं। कांग्रेस के लिए यह बेहद बड़ा झटका था और तृणमूल कांग्रेस ने धीरे-धीरे कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने पहले कांग्रेस से विपक्ष की भूमिका छीनी और इसके बाद 2011 में सत्ता में आ गईं। तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आते ही बंगाल में कांग्रेस अपने निचले स्तर पर पहुंचना शुरू हो गई। उसके बाद रही सही कसर बीजेपी ने पूरी कर दी। बीजेपी 3 सीट से 77 तक पहुंच गई और टीएमसी के खिलाफ मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस सत्ता और प्रतिपक्ष की कुर्सी गंवाते हुए शून्य पर आ गई। बहरहाल, कांग्रेस की रणनीति से ममता बनर्जी का खेल बिगड़ेगा या फिर बीजेपी का गेम खराब होगा? क्या होगा, यह जानने के लिए 4 मई तक इंतजार करना होगा।

बंगाल में बढ़ती अराजकता लोकतंत्र के लिए चुनौती

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल, जो कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिकता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें लगातार कमजोर होती प्रतीत हो रही हैं। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य में हिंसा, अराजकता अलोकतांत्रिकता और राजनीतिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटते सम्मान और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है। हाल ही में मालदा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अर्थात एसएआर को लेकर जिस प्रकार का असंतोष और तनाव देखने को मिला, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए स्पष्ट नियम और प्रावधान होते हैं। यदि इस प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। एसएआर प्रक्रिया में बाधक बनते हुए जिसे तरह से न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना सामने आयी है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र के लिये एक गंभीर चेतावनी भी है। यह उस व्यापक घातक एवं विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को भी राजनीतिक दबाव और भीड़तंत्र के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से यह तथ्य कि बंधक बनाए गए अधिकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं, इस घटना को और अधिक गंभीर बना देता है। यह न केवल कानून के शासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, उसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद वामपंथी शासन के लंबे कालखंड में भी राजनीतिक विरोधियों के प्रति असहिष्णुता और

हिंसा की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहीं। सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस एवं ममता बनर्जी के शासन में यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में सामने आई। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या केवल किसी एक दल या विचारधारा की नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त एक गहरे संकट की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चुनावों के निकट आते ही जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में लगे अधिकारियों को बंधक बनाना यह दर्शाता है कि कुछ तत्व चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार पर सीधा हमला है।

इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता उल्लेखनीय है। समय-समय पर न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाई है। किंतु यह भी एक चिंताजनक तथ्य है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई देता। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य प्रशासन एवं सत्तारूढ पार्टी इन निर्देशों को लागू करने में अक्षम है या इच्छुक नहीं है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चुनाव के समय बढ़ती अराजकता के पीछे राजनीतिक बौखलाहट भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। जब किसी दल को अपनी लोकप्रियता में गिरावट का भय होता है, तो वह अक्सर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दरकिनार कर असंवैधानिक उपायों का सहारा लेने लगता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, जहां सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं पर विपक्ष को डराने, प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

नागरिक समाज सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति इन सभी पहलुओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि चुनाव प्रक्रिया ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नहीं रह जाती, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मतदाता का विश्वास होता है, और यदि मतदाता को यह लगने लगे कि मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया या प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता स्वत: कमजोर होने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक नाकामी का प्रश्न भी गंभीरता से सामने आता है। किसी भी राज्य में यदि अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, न्यायिक अधिकारी तक बंधक बना लिए जाते हैं और पुलिस या प्रशासन समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता, तो यह प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी का स्पष्ट प्रमाण है। प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना और सरकारी कार्यों को निर्भय वातावरण में संपन्न कराना होता है। यदि प्रशासन यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, तो इससे जनता में भय और अविश्वास दोनों बढ़ते हैं। जनता का विश्वास ही किसी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होता है, और जब यही विश्वास डगमगाने लगता है, तो शासन की वैधता पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं।

राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवाहक भी होते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को संयम, कानून के सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कटु संघर्ष में बदल जाती है और कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल चुनाव को युद्ध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्सव के रूप में देखें। आज आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं को केवल एक राज्य की समस्या न मानकर लोकतंत्र के लिए चेतावनी के रूप में देखा जाए। यदि प्रशासनिक तंत्र कमजोर होगा, राजनीतिक दल मर्यादा नहीं रखेंगे, और जनता का विश्वास कम होता जाएगा, तो लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान या न्यायालय नहीं कर सकते, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक निष्पक्षता और जनता की जागरूकताकृतीनों का संतुलन आवश्यक है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थितियां हमें यही संदेश देती हैं कि लोकतंत्र को केवल चुनाव से नहीं, बल्कि व्यवस्था की निष्पक्षता, कानून के शासन और नागरिक विश्वास से मजबूत बनाया जा सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि राज्य सरकार, चुनाव आयोग और न्यायपालिका मिलकर ठोस कदम उठाएं। कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए, दोषियों के खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई हो और प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें। निश्चित ही यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति एक चेतावनी है कि यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह अराजकता और गहराई तक फैल सकती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हम सभी मिलकर कानून, नैतिकता और सहिष्णुता के मूल्यों को पुन: स्थापित करें। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से वह या तो लोकतांत्रिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ सकता है या अराजकता के गहरे गर्त में गिर सकता है। यह निर्णय न केवल राजनीतिक नेतृत्व, बल्कि पूरे समाज को मिलकर लेना होगा।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्याय: (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

इन्द्रस्तु मेषवृषणस्तदाप्रभृति राघव!।
गोत्तमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मन: ।।10।।
(वाल्मीकीय रामायण बालसर्ग 46)
(ख) तदा गोत्तमशापेन भगाङ्गश्च बभूव स: ।।8।।
रवेर्वरेण शक्र: स सहस्राक्षो बभूव ह ॥10।।
(ब्रह्मवैवर्त कृ0 ज0 खं0 अध्याय 61)

अर्थात् (क) [गोत्तम के शाप से वृषणरहित हुये इन्द्र ने अग्नि ग्रादि सब देवताओं को और सिद्ध गन्धर्व चारणों को भयविह्वल होकर कहा॥1॥ [कि महात्मा गोत्तम के तप को भङ्ग करते हुये मैंने उनके हृदय में क्रोध को जगा कर समस्त देवताओं का काम बना।

* टिप्पणी-पुराणों में सहस्रभग हो जाने का उल्लेख और वाल्मीकिरामायण में वृषणरहित हो जाना लिखा है। अध्यात्म रामायण (बालसर्ग 4 टिप्पणी में इस विरोध का कल्पान्तर व्यवस्था से परिहार किया है। ॥2॥ क्रूद्ध होकर गोत्तम जी ने मुझे वृषणरहित बना दिया, और अपनी स्त्री को भी [पाषाण-शिला बना कर] निराकृत किया। पश्चात् बड़ा भारी शापानुग्रह करवा कर भी मैंने [दोनों प्रकार से] उनके दपोबल का अपहरण किया है।।।3।।

इसलिए अब आप सब देव ऋषि चारण आदि महानुभाव देव-कार्य करने वाले मुझ को किसी प्रकार पुन: वृष सहित बनावें ॥4।। तब शतक्रतु इन्द्र के ऐसे वचन सुन अग्नि आदि देवता मरुद्गण सहित पितृ-देवताओं के पास जा कर कहने लगे [कि] ॥5।। देवराज वृषणरहित हो गये, परतु यह मेष (मेंढा) वृषण वाला है इसलिए आप इस मेंढे के वृषण लेकर शीघ्र ही इन्द्र के अङ्ग में जोड़ दीजिये।।6।। अग्निदेव की आज्ञा को सुनकर पितृदेवताओं ने इकट्ठे होकर मैंढे के अण्डकोश निकाल कर इन्द्र के देह में जोड़ दिये ॥8॥

क्रमशः ...

विश्व स्वास्थ्य दिवस

मुकेश कुमार शर्मा

राष्ट्र की उन्नति के लिए हर किसी का पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं खुशहाल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ नागरिकों से ही समृद्ध राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। यही कारण है कि स्वस्थ स्वास्थ्य व्यवहार अपनाने के प्रति जागरूकता के लिए ही हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस यानि सात अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मूल मकसद लोगों को स्वस्थ जीवनयापन के लिए जरूरी परामर्श प्रदान करने के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है।

शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ ही मानसिक रूप से भी पूर्ण स्वस्थ होना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सही पोषण के साथ ही ध्यान, योग और प्राणायाम को

भी जीवन में जरूर शामिल किया जाए। आज शारीरिक श्रम से नाता तोड़ने का ही परिणाम है कि तरह-तरह की बीमारियाँ मानव शरीर पर कब्ज़ा जमाती जा रहीं हैं। चिकित्सकों की भी यही सलाह रहती है कि गैर संचारी रोगों से बचना है तो रोजाना कम से कम 45 मिनट तक कड़ी मेहनत व शारीरिक श्रम जरूर करें। इससे तेजी से पैर पसार रहे हृदय रोग और डायबिटीज से सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा बीड़ी-सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों और शराब से दूरी बनाने में ही सभी की भलाई है क्योंकि कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियां इन्हीं से पैदा होती हैं। गैर संचारी रोगों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ही घर के करीब में आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) स्थापित किये गए हैं। इन केन्द्रों पर इन बीमारियों की स्क्रीनिंग, जांच और परामर्श के लिए कम्युनिटी हेल्थ आफिसर (सीएचओ) की तैनाती की गयी है। इसलिए जब भी कुछ असहज महसूस करें तो अप्रशिक्षित चिकित्सकों के पास जाने के बजाय बेहिचक सीएचओ की मदद लें, जो सही मायने में आपके सच्चे मददगार साबित होंगे।

अपने ही देश नहीं बल्कि विदेशों में भी आज की भागदौड़ भरी जिन्दगी और बदलती जीवन शैली ने सबसे अधिक युवा पीढ़ी को प्रभावित किया है। जीवन में जल्दी से जल्दी सब कुछ हासिल कर लेने की चाह ने जहाँ युवाओं के सुकून को छीना है वहीँ उनके पास न तो सही वक्त पर खाना खाने का समय है और न ही सोने का। यही कारण है कि फ़ास्ट फूड और दिखावे के लिए शराब और सिगरेट का सहारा लेने वाले युवाओं में हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर और हाइपरटेंशन जैसे गंभीर गैर संचारी रोग अब 30 साल की उम्र में ही शरीर पर कब्ज़ा जमाने लगे हैं।

स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है कि भोजन संतुलित मात्र में ही करें और उसमें फल और हरी सब्जियों को जरूर शामिल करें। शरीर को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। इसके अलावा तनाव से दूर रहें और कभी भी कोई परेशानी महसूस हो तो परिवार वालों से जरूर साझा करें। प्रतिदिन कम से कम छह से सात घंटे की नींद लें और आराम करें।

युद्ध अपराधी है डोनॉल्ड ट्रंप व नेतन्याहू

तनवीर जाफ़री

अमेरिका व इस्राईल द्वारा संयुक्त सैन्य अभियान चलाकर ईरान पर थोपे गये बलात युद्ध को पांच सप्ताह बीत चुके हैं। पूरी दुनिया में अपनी फ़ज़ीहत होती देख राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप ने अब खिसियाहट में ईरान के आधारभूत ढांचों को नुक़सान पहुँचाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने पिछले दिनों ईरान की राजधानी तेहरान और कराज़ को जोड़ने के लिए बनाये जा रहे राजधानी के सबसे ऊँचे सस्पेंशन ब्रिज को ध्वस्त कर दिया। लगभग 1 किलोमीटर से अधिक लंबे और 136 मीटर ऊँचे इस निर्माणाधीन हाई-राइज़ ब्रिज पर पिछले दिनों अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर दो बार एयरस्ट्राइक की। इन हवाई हमलों के परिणामस्वरूप पुल का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। इस हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। इस हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस पुल के ढहते हुए वीडियो शेयर कर ईरान को धमकी देते हुये लिखा कि डील कर लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने लिखा कि अगर ईरान ने अपना रुख़ नहीं बदला तो उस देश में कुछ भी नहीं बचेगा जो कभी महान देश बन सकता था,। ट्रंप ने इस हमले को अमेरिकी सेना की ताक़त का छोटा नमूना बताया और यह संकेत दिया कि अगर ईरान डील से मना करता है तो देश के पावर प्लांट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आदि अन्य इंफ़्रास्ट्रक्चर भी अगले निशाने हो सकते हैं।

इसी अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत में 28 फ़रवरी को ही ईरान के मिनाब शहर में शजारेह तैय्येबह बालिका प्राथमिक स्कूल की ईमारत पर टॉमहॉक मिसाइल मिसाइल से हमला कर लगभग 175 लोगों को शहीद कर दिया था इनमें अधिकांश स्कूल की बच्चियां शामिल थीं। स्कूल के पास ही दवाख़ाना व अन्य नागरिक सुविधाएं भी थीं। इसी हमले के चलते न केवल ईरान ने अमेरिका को युद्ध अपराध का दोषी ठहरा दिया था बल्कि दुनिया भर में भी इसे युद्ध अपराध क़रार दिया गया। ग़ौरतलब है कि

अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के मूल सिद्धांतों के तहत जिनेवा कन्वेंशन्स 1949 व इसके एडिशनल प्रोटोकॉल्स 1977 के अंतर्गत युद्ध में रिहाइशी इलाक़ों, स्कूलों, अस्पताल, पानी की व्यवस्था संबंधित प्लांट्स, बिजली ग्रिड,पुल जैसे बुनियादी ढांचों पर हमले सामान्यत: नहीं किए जा सकते। ये युद्ध अपराध माने जाते हैं। युद्ध में लड़ाई के दौरान सैनिकों,सैन्य लक्ष्यों और नागरिकों व नागरिक सुविधा संबंधी वस्तुओं के बीच स्पष्ट अंतर करना ज़रूरी है।? परन्तु अमेरिका तो क्या उसकी शह व संरक्षण में युद्धरत इस्राइल को भी न तो मानवीय क़ानून की फ़िक्र है न ही जिनेवा कन्वेंशन्स में निर्धारित युद्ध के सिद्धांतों की। इसीलिये अपनी अपार शक्ति व सर्वोच्चता के नशे में चूर अमेरिका व उसके पिछलग्गू इस्राईल द्वारा हर संभव युद्ध अपराध किया जा रहा है।

गज़ा में तो नेतन्याहू के नेतृत्व में इस्राईल ने दरिन्दिगी का वह इतिहास रचा है जिसने युद्ध अपराध की सभी सीमाओं को पार कर दिया है। सरकारी आंकड़े बताते है कि 7 अक्टूबर 2023 से 25 मार्च 2026 तक इस्राईली सेना द्वारा 72,265 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं जबकि 1,71,959 लोग घायल हुए। यहाँ तक कि 10 अक्टूबर 2025 को लागू हुये युद्धविराम के बाद भी इस्राईल ने लगभग 700 लोगों को मार दिया है। हालाँकि कुछ स्वतंत्र अध्ययन कुल मौतों का आंकड़ा 75,000 से ज़्यादा बता रहे हैं। स्वयं इस्राइली सेना ने जनवरी 2026 में 70,000 मौतों का आंकड़ा स्वीकार किया था। कुल लगभग 22-23 लाख की आबादी वाले इस इलाक़े में 19 लाख से ज़्यादा लोग एक या कई बार विस्थापित हुए हैं। नतीजतन आज भी 17 लाख से ज़्यादा लोग अस्थायी विस्थापन कैंप्स में रह रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों के घर-मकान नष्ट हो चुके हैं जिसके चलते लोग बेघर हैं। नेतन्याहू के इशारों पर यह हत्याएं घने रिहायशी इलाक़ों,स्कूल्स,बाज़ार,अस्पताल,स्कूल यहाँ तक कि शरणार्थी कैम्पस में और भूख की तपिश से जूझ रहे खाद्य सामग्री लेने की लाइन में लगे असहाय लोगों पर बम व गोले बरसा कर उनकी जान लेकर की गयी हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू पर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराध वारंट जारी किया हुआ है। नेतन्याहू पर भुखमरी को युद्ध का हथियार बनाना, जानबूझकर नागरिक आबादी पर हमला निर्देशित करना,मानवता के ख़िलाफ़ अपराध,हत्या,उत्पीड़न व अन्य अमानवीय कृत्य जैसे युद्ध अपराध शामिल हैं। आज भी नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के भगौड़े अपराधियों की श्रेणी में शामिल हैं। परन्तु युद्ध अपराधी भगौड़ा नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता। उल्टे इसे यहूदी-विरोधी तथा राजनीतिक साज़िश बताकर अपने युद्ध अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश करता है।

इसी युद्ध अपराधी नेतन्याहू के जाल में फंसकर राष्ट्रपति ट्रंप भी युद्ध अपराध करते जा रहे हैं। ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की उनकी धमकी इस बात का सुबूत है कि ऐसे मानसिक रोगी राजनीतिज्ञ की जगह जेल में होनी चाहिये। दुनिया को यह सोचना पड़ेगा कि आख़िर क्या वजह है कि उनके सलाहकारों से लेकर सैन्य विभाग के अनेक बड़े अधिकारी तक इस अवैध युद्ध का विरोध करते हुये क्योंकर इस सनकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खड़े होने के बजाये अपने इस्तीफ़े दे रहे हैं।

नाटो सहित उसके कई सहयोगी देश खुलकर ट्रंप के ईरान में सैन्य हस्तक्षेप का विरोध कर रहे हैं। और आज ईरान की ताक़त व उसकी रक्षात्मक व आक्रामक शक्ति का अंदाज़ा किये बिना ईरान पर हमला बोल देने और परणामस्वरूप अमेरिका द्वारा ऐतिहासिक क्षति का सामना करने से अमेरिका के महाशक्ति होने का जो भरम टूटा है उसका ज़िम्मेदार भी ट्रंप ही है। और इसी सन्दर्भ में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची को यह कहना पड़ा है कि -अधूरे बने पुलों समेत इंफ्रास्टक्चर पर हो रहे हमले ईरानियों को सरेंडर करने के लिये मजबूर नहीं कर सकते। यह केवल अव्यवस्था में फंसे दुश्मन की हार और उस के नैतिक पतन को दिखाता है। साथ ही अरागची ने यह भी कहा कि हर पुल और ईमारत को पहले से ज़्यादा मज़बूती के साथ बनाया जायेगा। परन्तु जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पायेगी वह है अमेरिकी साख को हुआ नुक़सान।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने भी अमेरिकियों के नाम एक खुला पत्र लिखकर कहा है कि वे युद्ध के प्रोपेगैंडा के धुंध से बाहर देखें और मनगढ़ंत ख़तरे को नकारें। राष्ट्रपति पेज़ेश्कियन ने सवाल उठाया है कि क्या अमेरिका सचमुच अमेरिका फ़र्स्ट को आगे रख रहा है या फिर वह केवल इज़रायल के लिए एक प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है? पेज़ेश्कियन ने आगे कहा कि ईरानियों के मन में अमेरिका, यूरोप या किसी भी पड़ोसी देश के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है। परन्तु सच्चाई तो यही है कि युद्ध अपराधी भगौड़े नेतन्याहू के चक्रव्यूह में उलझकर ट्रंप ने भी युद्ध अपराध को हीअंजाम दिया है। गोया डोनॉल्ड ट्रंप व नेतन्याहू दोनों ही युद्ध अपराधी हैं।

आज का इतिहास

1856 नेल्सन कॉलेज की स्थापना न्यूज़ीलैंड में की गयी।
1862 अमेरिकी गृहयुद्ध-संघ की सेना ने उस समय के अमेरिकी इतिहास में टेनेसी के शिल्लोह में कन्फेडरेट्स को हरा दिया था, जो उस समय हेनरी काउंटी, टेनेसी में था।
1928 हेरोल्ड लॉयड मूक कॉमेडी फिल्म स्पीडी जारी की गई।
1940 एजुकेटर बुकर टी. वाशिंगटन पहला अमेरिकी अमेरिकी बन गया, जिसे अमेरिकी डाक टिकट पर चित्रित किया गया।
1946 सीरिया को फ्रांस से आजादी मिली।
1947 अरब बाथ पार्टी की स्थापना दमिश्क में हुई।
1948 शंघाई में एक बौद्ध मठ में आग लगने से 20 बौद्ध भिक्षुओं मरे गए।
1948 संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य पर समन्वय प्राधिकरण के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की।
1955 वाकिफ है कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से बुढ़ापे में दोनों को धीमा कर रहा था, विंस्टन चर्चिल संयुक्त राज्य के प्रधान मंत्री के रूप में सेवानिवृत्त हुए।
1956 स्पेन ने मोरक्को में अपने रक्षक को छोड़ दिया।
1981 टेक्सास के कॉर्पस क्रिस्टी शहर में एक अनाज की लिफ्ट में विस्फोट होने से 9 लोग मारे गए और 30 घायल हुए।
1990 नॉर्वे के निकट एक नौका दुर्घटना में 110 लोग मारे गए, 30 उसी दिन शनिवार को बर्मा में एक नौका पलटने से मारे गए। नॉर्वेजियन सी में सोविएट सब डूब गया। हादसे में करीब 12 लोग मारे गए थे।
1991 'शैडो लैंड्स' न्यूयॉर्क शहर में परिजनों के बेटे थिएटर में बंद था। यह लगभग 5 महीने तक हाउसफुल चला।
1991 बॉब नाइट, लैरी ओ ब्रायन, टाइनी आर्चीबाल्ड, डेव कॉन्सेंस, हैरी गैलैटिन और लैरी फ्लेशर को एनबीए हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया।
1994 रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनल हेव्यारिमाना एवं बुरुंडी के राष्ट्रपति सिप्रियन न्तायमिटा का किगाली हवाई अड्डे पर राकेट हमले में निधन।
1994 बिग लव न्यूयॉर्क शहर में प्लाई महीने के थिएटर में बंद था। यह 41 दिनों तक हाउसफुल चला।
1994 फेडएक्स एक्सप्रेस के एक कर्मचारी ने असफल आत्महत्या के प्रयास में फेडरल एक्सप्रेस फ्लाइट 705 को हाईजैक करने की कोशिश की।
1994 रवांडा नरसंहार शुरू हुआ, हत्या के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति जुवेनाइल हबरिमाना; अगले 100 दिनों में अनुमानित 500,000-1,000,000 रवांडा मारे गए।

5 राज्यों के विधान सभा के चुनावी समरक्षेत्र में जनादेश की आहट

बिनोद कुमार सिंह

भारत का लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं,बल्कि एक जीवंत परंपरा है,जहाँ प्रत्येक चुनाव जनभावनाओं का उत्सव बनकर सामने आता है। वर्ष 2026 में पाँच राज्यों-असम,तमिलनाडु,केरल, पश्चिम बंगाल और मणिपुर-के चुनाव इसी लोकतांत्रिक परंपरा के निर्णायक अध्याय बनकर उभरे हैं। यह केवल सत्ता परिवर्तन का अवसर नहीं,बल्कि पिछले पाँच वर्षों के कार्यों,वादों और जनता के विश्वास की अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है।इन राज्यों की जनता ने बीते वर्षों में विकास,महंगाई,रोजगार,शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को नजदीक से महसूस किया है।

अब जब चुनावी शंखनाद हो चुका है,राज्यों के मतदाता अपने मन में एक ठोस निर्णय बना चुका है।वह यह तय करने की स्थिति में है कि कौन उसके सपनों का संवाहक है और कौन केवल राजनीतिक वादों का व्यापारी है।भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि मतदाता अब पहले से कहीं अधिक सजग, जागरूक और निर्णायक हो गया है।वह जातीय और धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर सुशासन और विकास को प्राथमिकता देने लगा है।यही कारण है कि इस बार 5 राज्यों के विधान सभा चुनावों में पारंपरिक समीकरणों के साथ-साथ प्रदर्शन आधारित राजनीति भी प्रमुख भूमिका में दिखाई दे रही है।चुनावी मैदान आज एक ऐसे समरक्षेत्र में बदल चुका है,जहाँ सत्तारूढ़ राजनीतिक दल अपनी उपलब्धियों के रथ पर सवार है, वहीं विपक्ष असंतोष और सवालों के शस्त्र लेकर चुनावी मैदान में उतरा है।

अगर हम राजनीतिक परिदृश्य पर एक दृष्टि डालें तो हर राज्य की परिस्थितियाँ भिन्न होते हुए भी एक समानता स्पष्ट दिखाई देती है-सत्ता और विपक्ष के बीच सीधा और तीखा संघर्ष का दौर जारी है।सत्तारूढ़ दल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए बुनियादी ढांचे के विकास,कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों को जनता के सामने रख रहा है। डबल इंजन जैसे राजनीतिक नारे और योजनाओं का लाभ उठाने वाला वर्ग उसके समर्थन का मजबूत आधार बन चुका है।वही दूसरी ओर विपक्ष महंगाई,बेरोजगारी,किसान संकट और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में जुटा है और जनता को परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा है।

यदि इन पाँच राज्यों के चुनावी परिदृश्य को गहराई से देखा जाए, तो एक बहुआयामी तस्वीर सामने आती है।असम में सत्ता पक्ष अपने मजबूत संगठन और नेतृत्व के कारण हल्की बढ़त बनाए हुए है। यहाँ उसे लगभग 44 से 48 प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है,जबकि विपक्ष 40 से 43 प्रतिशत के बीच सिमट सकता है।सीटों के रूपांतरण में यह अंतर सत्ता पक्ष को बढ़त दिला सकता है,जहाँ 126 सदस्यीय विधानसभा में उसके 68 से 78 सीटों तक पहुँचने के संकेत मिलते हैं।इसके बावजूद मुकाबला पूरी तरह एकतरफा नहीं है और विपक्ष की चुनौती मजबूत बनी हुई है।

वही तमिलनाडु में राजनीति अपने पारंपरिक द्रविड़ स्वरूप में ही दिखाई देती है,जहाँ डीएमके गठबंधन लगभग 42 से 46 प्रतिशत वोट हासिल कर स्पष्ट बढ़त की स्थिति में नजर आता है। एआईएडीएमके गठबंधन 34 से 38 प्रतिशत के बीच सीमित रह सकता है,जबकि अन्य दलों का प्रभाव सीमित दायरे में रहेगा। 234 सदस्यीय विधानसभा में डीएमके गठबंधन 140 से 160 सीटों के साथ सशक्त स्थिति में उभर सकता है,जो यह स्पष्ट संकेत देता है कि वहाँ सत्ता की निरंतरता संभव है।

केरल की राजनीति हमेशा से विचारधारात्मक संघर्ष और वैकल्पिक सत्ता परिवर्तन के लिए जानी जाती रही है,लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी भिन्न दिखाई देती है। एलडीएफ 43 से 46 प्रतिशत वोट के साथ बढ़त बनाए हुए है,जबकि यूडीएफ 41 से 44 प्रतिशत के बीच मुकाबले में बना हुआ है।140 सीटों वाली विधानसभा में एलडीएफ को 70 से 80 सीटों तक पहुँचने का अनुमान है,जो यह संकेत देता है कि परंपरागत ट्रेंड के विपरीत सत्ता की पुनरावृत्ति संभव हो सकती है।पश्चिम बंगाल का चुनावी परिदृश्य सबसे अधिक तीव्र और ध्रुवीकृत दिखाई देता है।यहाँ टीएमसी 44 से 47 प्रतिशत वोट के साथ आगे है,जबकि भाजपा 38 से 42 प्रतिशत के बीच मजबूत चुनौती दे रही है।294 सीटों वाली विधानसभा में टीएमसी को 160 से 190 सीटें मिलने की संभावना है,जबकि भाजपा 90 से 120 सीटों के बीच रह सकती है।यह परिणाम दर्शाता है कि सत्ता पक्ष को बढ़त तो है,लेकिन विपक्ष भी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कर रहा है। जहाँ तक केंद्र शासित

जहाँ तक मणिपुर की बात है तो मणिपुर में राजनीतिक समीकरण अधिक जटिल और स्थानीय प्रभावों पर आधारित हैं।यहाँ भाजपा 36 से 40 प्रतिशत वोट के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती है, जबकि कांग्रेस 30 से 34 प्रतिशत के बीच रह सकती है।क्षेत्रीय दलों का 20 से 25 प्रतिशत वोट इस चुनाव को त्रिशंकु स्थिति की ओर ले जा सकता है।60 सदस्यीय विधान सभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलना कठिन प्रतीत होता है और गठबंधन की राजनीति यहाँ निर्णायक भूमिका निभा सकती है।इन सभी 5 राज्यों के समेकित विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय चुनावी समीकरण में वोट प्रतिशत और सीटों का अनुपात हमेशा सीधा नहीं होता।कई बार केवल 2 से 3 प्रतिशत वोट का अंतर दर्जनों सीटों का अंतर बना देता है,जो सत्ता की दिशा बदलने में निर्णायक साबित होता है।ऐसे में क्षेत्रीय दल अभी भी कई राज्यों में राजनीति के केंद्र में हैं और राष्ट्रीय दलों के लिए चुनौती बने हुए हैं।

गठबंधन राजनीति का प्रभाव असम और मणिपुर जैसे राज्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है,जबकि तमिलनाडु,केरल और पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय नेतृत्व की पकड़ मजबूत बनी हुई है।

अगर हम चुनावी मुद्दों की बात करें तो महंगाई,रोजगार,कृषि संकट, युवा आकांक्षाएँ और महिला सशक्तिकरण जैसे विषय हर राज्य में गूंज रहे हैं।कोविड के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा भी प्रमुख मुद्दों के रूप में उभरे हैं।इसके साथ ही सोशल मीडिया ने चुनावी परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा प्रचार और संवाद अब चुनावी रणनीति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है।इन चुनावों का प्रभाव केवल इन राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेगा।वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से इसे एक प्रकार का सेमीफाइनल माना जा रहा है।यदि सत्तारूढ़ दल इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसकी राष्ट्रीय स्थिति और मजबूत होगी।वहीं विपक्ष के लिए यह अवसर है कि वह अपनी रणनीति को धार देकर आगामी चुनावों के लिए मजबूत आधार तैयार करे।

संक्षेप में, इस चुनावी महासमर में सबसे बड़ी शक्ति जनता ही है।वही इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक धुरी है,जिसके एक वोट से सत्ता का संतुलन बदल सकता है।यह चुनाव केवल सरकार चुनने का अवसर नहीं, बल्कि अपने भविष्य और अपने अधिकारों को दिशा देने का माध्यम है।पाँच राज्यों में सत्ता का संघर्ष और लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा की घड़ी ,जनता जनार्दन मौन है।राज्यों के मतदाताओं ने अपने मन में जो निर्णय लिया है,वह शीघ्र ही मतपेटियों के माध्यम से सामने आएगा और उसी के आधार पर तय होगा कि सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा।

चुनावी समरक्षेत्र में शंखनाद हो चुका है,रथ सज चुके हैं और राजनीतिक योद्धा मैदान में उतर चुके हैं।अब सबकी निगाहें उस अंतिम निर्णय पर टिकी हैं,जो जनता जर्नादन के हाथों में है।वही निर्णय आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करेगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि किसने जनादेश को समझा और किसे आत्ममंथन की राह चुननी पड़ी।

ट्रंप के संदेश से वैश्विक तनाव बढ़ा दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध के मुहाने पर?

सनत जैन

डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताजा संदेश दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस संदेश ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बड़ी हलचल तेज कर दी है। माना जा रहा था कि वह ईरान युद्ध को लेकर कोई स्पष्ट नीति की घोषणा करेंगे। लेकिन उन्होंने किस तरह का कोई बयान नहीं दिया। उनके बयान के बाद यह आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ है, उसके बाद दुनिया एक बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकती है। खासकर ईरान के खिलाफ कई देशों को एकजुट करने की बात ने वैश्विक संतुलन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मध्य-पूर्व पहले से ही युद्ध के कारण कई कारणों से अस्थिर है, जहां इसराइल ,इराक सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों के बीच जटिल स्थिति देखने को मिल रही है। यदि इन देशों के बीच युद्ध इसी तरह चलता रहेगा,तो इसका सबसे बड़ा असर इन्हीं देशों पर पड़ेगा। विशेष रूप से इराक और इजराइल को भारी जनहानि और आर्थिक नुकसान होना तय है।

इतिहास गवाह है, जब भी बड़ी शक्तियां टकराती हैं। तो इसका परिणाम वैश्विक आर्थिक संकट के रूप में सामने आता है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में यदि युद्ध की स्थिति बनती है, तो दुनिया में एक नई महामंदी की ओर बढ़ती दिख रही है। ऊर्जा आपूर्ति बाधित होगी, व्यापार ठप पड़ेगा और महंगाई चरम पर पहुंच सकती है। विश्लेषकों का मानना है, यह स्थिति वैसी ही हो सकती है।जैसी लगभग 36 साल पहले सोवियत यूनियन के विघटन के समय बनी थी। उसी की पुनरावृत्ति होती हुई दिख रही है। उस दौर में आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक दबाव ने सोवियत रूस का विघटन कर उस महाशक्ति को कमजोर कर दिया था। यदि अमेरिका लंबे समय तक किसी बड़े युद्ध में उलझता है। तो उसके आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए विश्व युद्ध का संकेत मान लेना जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं। उससे कभी भी विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान और वैश्विक शक्तियों एक तरह से निष्क्रिय हैं। जो हालात को नियंत्रित करने में भूमिका निभा सकते हैं। ट्रंप के बयान ने निश्चित रूप से दुनिया के सभी देशों की चिंता बढी हैं। वर्तमान में इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने की दिशा में ना तो वैश्विक संस्थाएं आगे आ रही हैं ना ही कोई ऐसा नेता अब है जो सब लोगों से बात करके संयम और विवेक से स्थिति को संभाल सके। इस समय आर्थिक मंदी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। दुनिया को युद्ध नहीं, बल्कि संवाद और सहयोग की जरूरत है। अमेरिका इजरायल और ईरान के युद्ध का असर दुनिया के सभी देशों पर पड रहा है। अन्यथा सारी दुनिया विनाश के मुहाने पर खड़ी हुई दिख रही है। वैश्विक संघर्ष का खामियाजा करोड़ों लोगों की आबादी को भुगतना पडेगा।

भाजपा के 47 साल : शिखर पर जीत, सिद्धांतों पर

दिलीप कुमार पाठक

6 अप्रैल 1980 को मुंबई के समंदर किनारे जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा का उद्घोष किया था, तो वह केवल एक चुनावी नारा नहीं बल्कि एक वैकल्पिक राजनीति का संकल्प था। आज 2026 में जब भारतीय जनता पार्टी अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वह दुनिया के सबसे बड़े और अजेय नजर आने वाले राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित हो चुकी है। लेकिन इस अभूतपूर्व सफलता के ऊंचे बुर्ज पर बैठकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो कुछ बुनियादी सवाल आज भी पार्टी की उस अलग तरह के दल वाली छवि का पीछा कर रहे हैं। क्या सत्ता के इस विशाल साम्राज्य को खड़ा करने की प्रक्रिया में वे आदर्श कहीं पीछे छूट गए हैं, जो इस दल की नींव में रखे गए थे? भारतीय राजनीति के इस लंबे सफर में भाजपा ने शून्य से शिखर तक की जो यात्रा तय की है, वह संगठनात्मक कौशल का अद्भुत उदाहरण तो है, पर क्या यह सफर अपनी मूल शुचिता को भी साथ लेकर चल पाया है?

भाजपा की वैचारिक यात्रा का मूल आधार अंत्योदय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दो मजबूत स्तंभ थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि विकास की कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय हो। हालांकि, उज्ज्वला से लेकर मुफ्त राशन और सीधे बैंक खातों में मदद जैसी बड़ी योजनाओं ने एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार किया है, जिसे पार्टी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। लेकिन क्या कल्याणकारी योजनाओं का यह दाता और याचक वाला मॉडल असल सशक्तिकरण है? आज की राजनीति सेवा से ज्यादा आयोजन प्रबंधन और डिजिटल प्रचार पर टिकी नजर आती है। जिस नैतिक बल और सादगी की मिसाल पुराने दौर के नेता देते थे, उसकी जगह अब चकाचौंध और भारी-भरकम चुनावी मशीनरी ने ले ली है। विकास के दावों के बीच यह सवाल अक्सर दबी जुबान में पूछा जाता है कि क्या हम बुनियादी मुद्दों के बजाय केवल भावनात्मक और सांकेतिक राजनीति के जाल में तो नहीं उलझ गए हैं?

एक जीवंत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना कि एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार का होना। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष मुक्त भारत की जिस अवधारणा को हवा दी गई, उसने लोकतांत्रिक संतुलन को बुरी तरह असहज किया है। जांच एजेंसियों के बढ़ते प्रभाव और विपक्षी नेताओं का बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल होकर रातों-रात पवित्र हो जाना, पार्टी की उस शुचिता पर गहरा सवालिया निशान लगाता है जिसका दावा वह दशकों से करती आई है। क्या सत्ता पाने की व्याकुलता में किसी भी दल के दागी चेहरों को अपना लेना उस कार्यकर्ता आधारित संगठन के लिए सही है, जो कभी अपने सिद्धांतों पर गर्व करता था? आज पार्टी का ढांचा भी पहले की तुलना में अधिक व्यक्ति-केंद्रित हो गया है। सामूहिक नेतृत्व और आंतरिक विमर्श की जगह अब केवल ऊपर से आने वाले आदेशों और हां में हां मिलाने वाली संस्कृति ने ले ली है।

राम मंदिर का निर्माण, अनुच्छेद 370 का खात्मा और नागरिकता कानूनों जैसे मुद्दों पर उसे व्यापक जनसमर्थन मिला है, लेकिन क्या राष्ट्रवाद की इस प्रबल लहर ने देश की बुनियादी आर्थिक चुनौतियों को कालीन के नीचे धकेल दिया है? बढ़ती बेरोजगारी, मध्यम वर्ग पर महंगाई का लगातार बढ़ता बोझ और अमीर-गरीब के बीच बढ़ती गहरी खाई ऐसे कड़वे सच हैं, जिन्हें केवल भव्य आयोजनों और नारों से नहीं बदला जा सकता। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तब तक अधूरा है जब तक देश का शिक्षित युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहा है। बड़े व्यापारिक घरानों के साथ बढ़ती नजदीकियों ने भी यह धारणा पुख्ता की है कि पार्टी का झुकाव अब आम आदमी से हटकर खास प्रबंधकों की ओर हो गया है।

स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर भाजपा को गहराई से आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या वह केवल चुनाव जीतने वाली एक पेशेवर मशीन बनकर रहना चाहती है या वापस उस नैतिक राजनीति की ओर लौटेगी, जिसका वादा 1980 के मुंबई अधिवेशन में किया गया था? लोकतंत्र केवल बहुमत का नाम नहीं है, यह अल्पमत के सम्मान, आलोचना को पचाने की शक्ति और संस्थाओं की स्वायत्तता का नाम भी है। यदि भाजपा को आने वाले दशकों में अपनी साख और गौरवशाली इतिहास को बचाए रखना है, तो उसे अपनी जीत के अहंकार से ऊपर उठकर उन लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से गले लगाना होगा, जो उसकी स्थापना की मूल भावना थे। सत्ता तो आती-जाती रहती है, लेकिन जो विचार अपनी नैतिकता और लोक-लाज की परवाह करना छोड़ देता है, वह इतिहास की नजरों में अपनी चमक धीरे-धीरे खोने लगता है। आने वाला समय बताएगा कि कमल की यह पंखुड़ियाँ सिद्धांतों की महक फैलाती हैं या केवल सत्ता की धूप में मुरझा कर रह जाती हैं।

उत्तराखंड में हरीश रावत के बिना बेमायने है कांग्रेस!

डॉ श्रीगोपाल नारसन

उत्तराखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय कांग्रेस नेता हरीश रावत एक मात्र ऐसे नेता है जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच सदैव सक्रिय रहते है।उनके बिना कांग्रेस बेमायने ही कही जाएगी।आजकल कांग्रेस प्रभारी शैलजा से अप्रत्यक्ष नाराजगी के चलते हरीश रावत ने अर्जित अवकाश की राजनीति शुरू की है।जिसे लेकर कांग्रेस के आला अधिकारी से लेकर कांग्रेस समर्थक भी असमंजस में है।

अपनी बढ़ती उम्र में भी बेहद सक्रिय कांग्रेस के शीर्ष नेता हरीश रावत के पास वर्तमान में कोई ठोस दायित्व नही है,फिर भी वे राज्य के सर्वाधिक सक्रिय नेता कहे जा सकते है।ऐसे में उनकी अनदेखी करके कांग्रेस कोई भी चुनाव फिलहाल नही लड़ सकती और यदि ऐसा हुआ तो फिर से कांग्रेस की लुटिया डूबने में देर नही लगेगी।पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा भी है कि वे पार्टी के लिए बूथ अध्यक्ष तक बनने को तैयार है। कांग्रेस ही नही अन्य राजनीतिक दलों को भी उत्तराखंड के इस सर्वमान्य नेता का सम्मान करना चाहिए।पिछले दिनों हरीश रावत का यह कहना भी गलत नही है कि कांग्रेस में कुछ लोग जहरीले हैं,ऐसे लोग बीजेपी में भी हैं। हरीश रावत ने हाल ही में कांग्रेस से कहा कि,मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरा काम है खांसते रहना ताकि कोई गलत आदमी पार्टी में न घुस पाए।उन्होंने पार्टी के साथ दगा करने वाले एक नेता कि ओर इशारा कर कहा कि, आपके पास जो भी जहर है, वो मेरे ऊपर डाल दो, मैं उसे पी जाऊंगा,आप बस एक-दूसरे की तारीफ करो, एक-दूसरे को प्रोत्साहित करो और आगे बढ़ो।

वास्तव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने कांग्रेस की मौजूद चुनौती को साफ दिखती है, गुटों में बंटी कांग्रेस इकाई का नेतृत्व करना, वह भी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बेहद कठिन कहा जा सकता है।वह भी तब जब कांग्रेस पार्टी सन 2017 और सन 2022 के दो विधानसभा चुनाव हार चुकी हो, साथ ही राज्य की लगातार तीन लोकसभा चुनावों में भी एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई है,जो पार्टी की कमजोर हालत को प्रमाणित करता है। दो बार के विधायक गणेश गोदियाल, जिन्हें कभी हरीश रावत का करीबी माना जाता था,का पुन: पदारूढ़ होने से उम्मीद है कि वे हरीश रावत को अपने से भी आगे करके चलेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वह राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके है, लेकिन उनके चुनाव हारने के बाद उनकी जगह करन माहरा को दे दी गई,परन्तु कांग्रेस कोई चमत्कार नही कर पाई।

हरीश रावत ने स्वयं को पीछे करते हुए सार्वजनिक रूप से सुझाव दिया था कि अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस को प्रीतम सिंह (जो पांच बार के विधायक हैं) के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। उनका यह बयान पार्टी में एकता का पहला कदम कहा जा सकता है।जब कांग्रेस उत्तराखंड में सत्ता में थी, तब भी हरीश रावत लगातार संघर्षों में फंसे रहे, पहले एन.डी. तिवारी को उनका हक दे दिया गया,जिससे टकराव की स्तिथि बनी रही और बाद में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को बनाकर फिर से हरीश रावत को किनारे करने की कोशिश की गई।लेकिन प्राकृतिक आपदा में विजय बहुगुणा के फेल हो जाने के कारण उनकी जगह सन 2014 में हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद पर रिप्लेस किया गया।यह बदलाव उस समय आया जब विजय बहुगुणा पर जून 2013 की केदारनाथ आपदा से निपटने को लेकर भारी आलोचना हो रही थी क्योंकि आपदा के समय विजय उत्तराखंड के बजाए दिल्ली में डेरा डाले हुए थे।

हाल ही में माहरा को सीडब्ल्यूसी और प्रीतम सिंह को सीईसी में शामिल किया जाना, कांग्रेस हाईकमान द्वारा राज्य में प्रतिस्पर्धी गुटों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, इसे हरीश रावत को उनकी नाखुशी के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व से जोड़कर रखने की रणनीति भी माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल से अनुरोध किया है कि उन्हें किसी बूथ का इंचार्ज बनाया जाए,हरीश रावत का कहना है कि वे ज़मीनी स्तर पर जाकर पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि उनकी ये बातें तंज या उन्हें किनारे किए जाने की नाराज़गी दिखाती हैं।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बात दोहराई और साफ कहा कि उनकी टिप्पणी को 'पावर मूव' यानी शक्ति प्रदर्शन के रूप में न देखा जाए,रावत ने लिखा, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, आज भी मेरे समर्थक इसे अपने तरीके से परिभाषित करते हैं और मेरे आलोचक अपने तरीके से।जब पार्टी एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है, तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं उसे ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए अपनी सेवाएं दूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के स्थायी आमंत्रित सदस्य हरीश रावत ने ये भी जोर दिया कि आज भी, वे खुद, करण मेहरा और प्रीतम सिंह—तीनों पार्टी के केंद्रीय स्तर पर ऊंचे पदों पर हैं, जहां करन माहरा सीडब्ल्यूसी में विशेष आमंत्रित सदस्य बने हैं, वहीं प्रीतम सिंह कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं।हरीश रावत ने, अपनी एक्स पोस्ट में हरक सिंह रावत को पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति का प्रमुख बनाए जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की है,जो उनकी धैर्यता का प्रमाण है,क्योंकि हरक सिंह रावत ने ही हरीश रावत सरकार गिराने के लिए भाजपा से हाथ मिलाकर कांग्रेस को उस समय धोखा दिया था।फिर भी हरीश रावत उन्हें बर्दाश्त कर रहे है यह कोई कम बात नही है।सन 2016 में, उस समय के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरक सिंह रावत पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दलबदल करवा कर उनकी सरकार गिराने की कोशिश की है, इसके बाद ही हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो गए थे और जनवरी 2022 तक वहीं रहे, जब भाजपा ने उन्हें बाहर कर दिया,तब वे फिर कांग्रेस में आए। हालांकि अब हरक सिंह रावत पुष्कर सिंह धामी सरकार के खिलाफ खुले तौर पर बोलते रहे हैं ।वे सीबीआई और ईडी के मामलों में कथित भ्रष्टाचार के आरोपी भी हैं।

11 टीएमसी उम्मीदवारों का भविष्य अधर में

सत्येंद्र प्रताप सिंह

बंगाल की मतदाता सूची चुनाव आयोग जब जारी किया था, उसमें 63 लाख 66 हजार 952 मतदाताओं के नाम कट गए थे। कहा गया कि यह या तो मृत पाए गए हैं या फिर कहीं अन्य राज्य में शिफ्ट हो चुके हैं। मार्के की बात तो यह है कि इसके साथ ही 60 लाख छह हजार 675 लोगों के नाम के आगे विचाराधीन लिखा हुआ था। ममता बनर्जी व उनकी पार्टी को यह विचलित करने के लिए काफी था। विचलित के बाद उत्तेजित तब हुई जब उन्हें यह पता चला कि उनकी सरकार में मंत्री शशि पांजा सहित 11 उम्मीदवारों का नाम ही मतदाता सूची में नहीं है। विचाराधीन मतदाताओं में से 46 लाख के करीब लोगों की जांच व तहकीकात पूरी हो चुकी है। प्रतिदिन दो लाख लोगों की जांच 705 ज्यूडिशियल ऑफिसर्स कर रहे हैं और 14 लाख लोगों की सुनवाई अभी तक शेष है। इसमें ममता सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री शशि पांजा सहित 11 उम्मीदवारों का नाम मतदाता सूची में ही नहीं है। शशि पांजा के अलावा टीएमसी के घोषित अन्य उम्मीदवार हैं, मोहम्मद गुलाम रब्बानी, मोहम्मद नजरुल इस्लाम, नूर आलम, डॉ अब्दुल अजीज, शाहिना मुमताज़, स्वाति खांडेकर, श्रीसंया बंदोपाध्याय, अनिसुर रहमान और फ़ैयाज़ शेख उर्फ काजल शेख। परिचय का इनका जहां तक सवाल है, शशि पांजा वरिष्ठ विधायक व महत्वपूर्ण विभाग की मंत्री हैं। कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व अजित पांजा की पुत्रवधु हैं। मोहम्मद गुलाम रब्बानी वरिष्ठ विधायक व राज्य सरकार के पूर्व मंत्री हैं। विधायक स्वाति खांडेकर पूर्व सांसद हैं व पूर्व सांसद स्व अकबर अली खांडेकर की पत्नी हैं। श्रीसंया बंदोपाध्याय, टीएमसी के वरिष्ठ सांसद व एडवोकेट कल्याण बनर्जी के बेटे हैं। फ़ैयाज़ शेख उर्फ काजल शेख वीरभूम जिला के वरिष्ठ व बाहुबली नेता हैं। गौ-तस्करी मामले में तिहाड़ जेल जा चुके वीरभूम जिला के ही बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल उर्फ केश्टो मंडल से इनका शुरू से छत्तीस का आंकड़ा रहा है। यानी यह वह लोग हैं जिन्हें लोग किसी न किसी कारण से जानते पहचानते जरूर हैं। ममता सरकार में ही मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कलकत्ता हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पॉल को तीन पेज का एक ईमेल भेजा है। जिसमें एसआईआर से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया है। इसमें एक पेज टीएमसी के इन 11 उम्मीदवारों को लेकर है कि इनका नाम विचाराधीन कब तक रहेगा। इन उम्मीदवारों के नाम, इनका विधानसभा सीट और इनके एपिक नम्बर के साथ यह लिखा गया है। चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा कलकत्ता हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस को ईमेल भेजने के पीछे की वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही कलकत्ता हाइकोर्ट के अधीन ज्यूडिशियल ऑफिसर्स विचाराधीन नामों की जांच कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल (सोमवार) है। टीएमसी के 6 उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उत्तर दिनाजपुर जिला के गोआलपुखुर सीट से मोहम्मद गुलाम रब्बानी, मालदा जिला के मोथाबाड़ी सीट से मोहम्मद नजरुल इस्लाम, मुर्शिदाबाद जिला के शमशेरगंज सीट से नूर आलम, लालगोला सीट से डॉ अब्दुल अजीज, नावदा सीट से शाहिना मुमताज और बीरभूम जिला के हासन सीट से फ़ैयाज़ हक उर्फ काजल शेख। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल (गुरुवार) है। दूसरे चरण में टीएमसी के 5 उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उत्तर 24 परगना जिला के देगंगा सीट से अनिसुर रहमान, हुगली जिला के चंडीतल्ला सीट से स्वाति खांडेकर, उत्तरपाड़ा सीट से श्रीसंया बंदोपाध्याय और कोलकाता के श्यामपुकुर सीट से शशि पांजा। बहरहाल, शशि पांजा की श्यामपुकुर सीट का जहां तक सवाल है, पिछले विधानसभा चुनाव में यह 22 हजार 520 मतों से विजयी हुई थीं। जबकि खबर है कि इस श्यामपुकुर सीट से एसआईआर में 51 हजार 918 मतदाताओं का नाम कट चुका है।

आशावादी बनिए

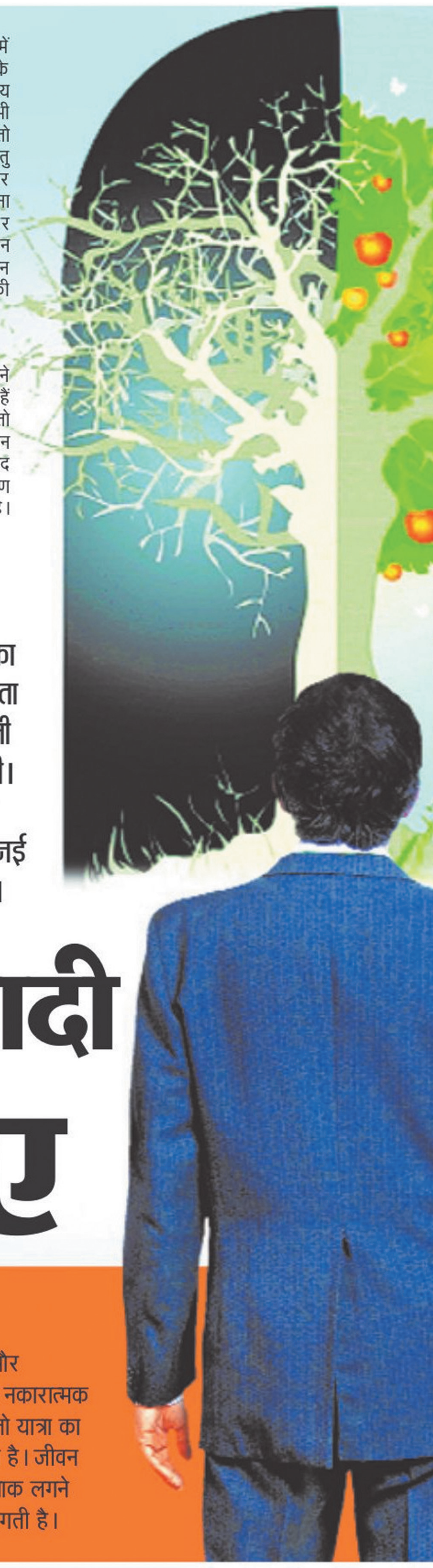

एडिसन की प्रयोगशाला एक अग्निकांड में पूरी तरह से जल कर ध्वस्त हो गई। उनके जीवन भर की शोध सामग्री और बहुमूल्य उपकरण सब खाक हो गए। आर्थिक क्षति भी बहुत हुई। यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उस हादसे से आसानी से उबर नहीं पाता, किंतु एडिसन ने कहा, इसमें हमारी भूलें भी जल कर नष्ट हो गई हैं। हमें ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए, अब हम नए सिरे से जीवन को शुरू कर सकते हैं। इन सब के बीच व्यक्ति की जीवन यात्रा उत्थान की दिशा में बढ़ रही है या पतन की दिशा में, इसमें उस व्यक्ति के दृष्टिकोण की भूमिका सबसे बड़ी होती है।

भाग्य को न कोसें

हम में से अधिकांश लोग ऐसी स्थिति में अपने दु:ख-दर्द एवं दुर्भाग्य के लिए भाग्य को कोसते हैं या फिर दूसरों को दोषी मानते हैं। और नहीं तो भगवान पर ही गुस्सा निकालने लगते हैं। एडिसन ने भगवान को कोसने की बजाय उसका धन्यवाद किया। जैसे ही हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है, तो स्थिति पलटने लगती है। आशा मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा है।

हमारे जीवन में प्रयास, पुरुषार्थ, अवरोध एवं संघर्ष का लगातार एक क्रम चलता रहता है। और ऐसे में सफलताएं भी मिलती हैं और विफलताएं भी। लेकिन अगर आप हमेशा आशावादी बने रहेंगे तो नित नई ऊंचाइयां प्राप्त करते रहेंगे।

आशा उत्साह की जननी

प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है, आशा उत्साह की जननी है। उसमें तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालन शक्ति है। यदि व्यक्ति आशा खो बैठता है तो जीवन नैया डूबने लगती है। आशा घोर अभाव और संकट के बीच भी निर्माण के तत्वों की खोज करती है। वह आभासित अभिशाप को भी वरदान में बदल देती है। ठीक इसके उलट, निराशावादी दृष्टिकोण के कारण हम अनुकूल अवसरों में भी प्रतिकूलता देखने लगते हैं। एडिसन आशावादी था, उसने अनुकूल अवसर खोजकर अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर लिया।

विफलता से मिलती है निराशा

इसलिए यदि घटनाएं हमारे अनुरूप नहीं घटतीं और हमें विफलता एवं निराशा का संदेश देती हैं, तो भी हिम्मत हारने एवं हताश होने की आवश्यकता नहीं। चाहे संघर्ष पथ पर हम गिर जाएं, पिट भी जाएं, तो भी यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। यदि लक्ष्य के प्रति मन में लगन हो, तो विफलता भी गिर कर फिर से उठकर खड़े होने और दुगुने उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

सफलताओं से सीखें

आशावादी व्यक्ति व्यावहारिक रुख अपनाते हुए अपने जीवन की छोटी - छोटी सफलताओं से क्रमश: आगे बढ़ता है। अपनी कार्यकुशलता और इच्छाशक्ति को क्रमश: विकसित करता जाता है। यह पद्धति रचनात्मकता का स्रोत बनकर उसे लगातार आगे बढ़ाती रहती है। निराशावादी व्यक्ति जहां एक दरवाजा बंद देखते ही अपना प्रयास छोड़ देता है, वहीं आशावादी व्यक्ति दूसरे खुले दरवाजों की तलाश में जुट जाता है। निराशावादी जहां सतत् हारता है, वहीं आशावादी अपनी तात्कालिक विफलताओं के बावजूद एक विजेता बन कर उभरता है। वास्तव में जब तक हम अपने जीवन के अर्थ एवं सुख की खोज के लिए बाहरी वस्तुओं, व्यक्तियों एवं परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं, तब तक निराशा का भाव भी बार-बार आता है। और जब दृष्टि अपने अंदर के मूल स्रोत की ओर मुड़ने लगती है, तो निराशा का कुहासा भी घटने लगता है।

हिम्मत न हारें

यदि हम छोटी-छोटी असफलताओं और रुकावटों से हिम्मत हार बैठते हैं और नकारात्मक भावों को जीवन में हावी होने देते हैं, तो यात्रा का हर कदम दूभर एवं कष्टप्रद बन जाता है। जीवन एक दु:खद घटना एवं दुर्भाग्यपूर्ण मजाक लगने लगता है। हमारी ऊर्जा कुंठित होने लगती है।

परमात्मा का वरदान

यहीं पर हमें परमात्मा की कृपा एवं वरदान की भाव भरी अनुभूति होती है। अपने ईमानदार प्रयास के साथ प्रभु प्रेम एवं उसके अचूक न्याय विधान के प्रति आस्था को धारण कर हम अनायास ही आस्तिकता एवं धार्मिकता के पथ पर बढ़ जाते हैं। वही हमें जीवन की सार्थकता के बोध की ओर ले चलती है।

प्रकृति का दास नहीं मनुष्य

ज्यों ही कोई विज्ञान पूर्ण एकता तक पहुंच जाएगा, त्यों ही उसकी प्रगति रुक जाएगी क्योंकि तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उदाहरणार्थ रसायनशास्त्र यदि एक बार उस मूल तत्त्व का पता लगा ले जिससे और सब द्रव्य बन सकते हैं तो फिर वह और आगे नहीं बढ़ेगा।

भौतिकी जब उस एक मूल शक्ति का पता लेगी, अन्य शक्तियां जिसकी अभिव्यक्ति हैं तब वह वहीं रुक जाएगी। वैसे ही धर्मशास्त्र भी उस समय पूर्णता को प्राप्त कर लेगा जब वह उसको खोज लेगा जो इस मृत्युलोक में एकमात्र जीवन है, जो इस परिवर्तनशील जगत का शाश्वत आधार है, जो एकमात्र परमात्मा है, अन्य सब आत्माएं जिसकी प्रतीयमान अभिव्यक्तियां हैं। इस प्रकार अनेकता और द्वैत में होते हुए इस परम अद्वैत की प्राप्ति होती है। धर्म इससे आगे नहीं जा सकता। यही समस्त विज्ञानों का चरम लक्ष्य है।

धर्म का प्रारंभ

धर्म का प्रारम्भ कैसे हुआ और वह क्रमश- विकास द्वारा आध्यात्मिक अद्वैतवाद की इस सीमा तक कैसे पहुंचा? क्या इसके बाद विचार के विकास पर विराम चिह्न लगा देना सम्भव है? मनुष्य मननशील प्राणी है। उसका मस्तिष्क अन्य सभी प्राणियों की अपेक्षा अधिक उन्नत है और यह मस्तिष्क ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जबकि दूसरे प्राणियों ने आत्मरक्षा की सहज प्रवृत्ति से अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाला है और निरन्तर ढालता जा रहा है। मनुष्य प्रकृति का दास नहीं विजेता है। उसने अपनी विचार-शक्ति द्वारा आग, पानी, बिजली का प्रयोग करके, शस्त्र-यंत्र का आविष्कार करके और प्रकृति के नियमों की खोज लगाकर अपनी इस विजय को सम्भव बनाया। प्रकृति को बदलने में वह स्वयं भी बदला। अपने इस संघर्ष में ही वह पशु से मनुष्य, हैवान से इंसान बना।

दैविक शक्ति का हाथ

मतलब है कि उसके निर्माण में किसी दैविक शक्ति का हाथ नहीं, बल्कि अपने इस संघर्ष के दौरान देव, दानव तथा ईश्वर आदि दैवी शक्तियों का निर्माण स्वयं उसने किया। सभी विचार भौतिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुए, मनुष्य ने उन्हें व्यवहार की कसौटी पर परखा। उनके असार तत्त्व को त्याग कर सारतत्त्व को भौतिक शक्ति में परिणत किया तथा सिद्धान्तों का रूप दिया।

प्रेम का कमल भक्ति

मन के साथ जो चला, वह कभी भगवान तक न पहुंच सकेगा। भगवान यानी जो है, भक्ति यानी जो है, उसे देखने की कला। लेकिन जो है, वह हमें दिखायी क्यों नहीं पड़ता? जो है वह तो हमें सहज दिखायी पड़ना चाहिए। जो है उसे खोजने की जरूरत ही क्यों हो? जो है उसे हम भूले ही क्यों, उसे हम भूले ही कैसे? जो है उसे हमने खोया कैसे? जो है उसे खोया कैसे जा सकता है?

इसलिए पहली बात समझ लेनी जरूरी है, मन का नियम। मन उसी को जानता है जो नहीं है। तुम्हारे पास अगर दस हजार रुपए हैं तो उन दस हजार रुपयों को मन भूल जाता है। मन उन दस लाख रुपयों का चिंतन करता है जो होने चाहिए, पर हैं नहीं। मन अभाव का चिंतन करता है। जो पत्नी उपलब्ध है, मन उसे भूल जाता है। जो स्त्री उपलब्ध नहीं है, मन उसकी कल्पनाएं करता है, योजनाएं बनाता है। जो मिला है, मन उसे देखता ही नहीं। उसी पर नजर रखता है, जो मिला नहीं है। हाथ की असलियत मन को नहीं भाती, स्वप्न के आभास भाते हैं। मन स्वप्न के भोजन पर जीता है। मन जीता ही स्वप्न के सहारे है।

भीतर सपनों का जाल

जब भी आंख बंद करोगे, भीतर सपनों का जाल पाओगे। आंख खोले काम में भी लगे हो, तब भी भीतर उनका सिलसिला जारी रहता है। तब भी पर्त-दर-पर्त सपने घने होते रहते हैं। तुम देखो या न देखो, लेकिन मन सपने बुनता रहता है। मन का सपनों का ताना-बाना क्षण भर को रुकता नहीं। उसी सपने के जाल का नाम माया है। उसी सपने के जाल में उलझे तुम परेशान और पीड़ित हो। जो नहीं है उसने तुम्हें अटकाया है। जो नहीं है, उसने तुम्हें भरमाया है। जो नहीं है उसने तुम्हारी आंखें बंद कर दी हैं और जो है उसे देखना मुश्किल हो गया है।

मन में श्रद्धा नहीं

रात तुमने कितनी बार सपने देखे हैं और हर बार जागकर पाया, झूठे थे! लेकिन फिर जब रात आज देखोगे स्वप्न तो देखते समय सच मानोगे। झूठ को सच मानने की तुम्हारी कितनी प्रगाढ़ धारणा है! कितनी बार जागकर भी, कितनी बार देखकर भी कि सपने सुबह झूठ सिद्ध हो जाते हैं, फिर भी जब तुम रात स्वप्न देखोगे तो सच मालूम होगा। लोग कहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा नहीं है। हम बड़े संवेदनशील हैं।

निस्तार कैसे होगा

हमारा निस्तार कैसे होगा? मैं कहता हूं, तुम सपनों तक पर श्रद्धा करते हो, सत्य की तो बात ही छोड़ो। तुम सपनों तक पर भरोसा करते हो, उन पर तक तुम्हें अभी सन्देह नहीं आया, तो तुम और किस पर सन्देह करोगे? जो नहीं है, उस पर भी सन्देह नहीं हो पाता, तो जो है उस पर तुम कैसे सन्देह करोगे? जिसने सपने तोड़े, उसके भीतर श्रद्धा का जन्म हुआ। जिसने सपने तोड़े, उसने तब सत्य को जानने का मार्ग साफ कर लिया।

बुद्धि नहीं हृदय की सुनिए

तुम्हारा हृदय ही कहेगा। हृदय हमेशा कह देता है, मगर तुम सुनते नहीं हो हृदय की। तुम कहते हो, कैसे गुरु को पहचानें? क्या कसौटी है? बुद्धि कसौटी मांगती है, हृदय तत्क्षण कह देता है, हृदय की सुनो, बुद्धि को एक तरफ रख दो।

हृदय से कभी भूल नहीं हुई है। हृदय ऐसे ही है, जैसे तुमने दिशासूचक-यंत्र, जो सदा बताता रहता है पूरब की ओर, सूरज उगने की ओर। हृदय सदा परमात्मा की तरफ इशारा करता है, मगर तुम हृदय नहीं बुद्धि की सुनते हो और बुद्धि की सुनने के कारण अक्सर भ्रांति में पड़ते हो। सच यह है कि जब तक बुद्धि की सुनते रहोगे, तब तक गुरु नहीं मिलेगा। जो मिलेंगे वे गुरु के धोखे होंगे। गुरु के धोखे बुद्धि को राजी कर लेंगे, क्योंकि गुरु के धोखे का मतलब होता है-जो तुम्हें राजी करने को ही बैठा है। तुम जैसा चाहते हो, वैसा बनकर बैठा है। सद्‌गुरु कभी भी तुम्हारी अभिलाषाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होता, हो ही नहीं सकता। नहीं तो जीसस को लोग सूली चढ़ाते? बुद्ध को पत्थर मारते? महावीर को गांव से खदेड़ कर निकालते? सुकरात को जहर पिलाते? यह मत सोचना कि वे सब लोग पागल थे। वे तुम्हारे ही जैसे लोग थे, तुम ही थे-जिन्होंने जीसस को सूली दी, सुकरात को जहर पिलाया, बुद्ध को पत्थर मारे, महावीर के कानों में सीखचे ठोक दिये। वे तुम से जरा भी भिन्न न थे। ऐसा नहीं है कि गुरुओं की पूजा उस दिन नहीं हो रही थी। जब बुद्ध को लोग पत्थर मार रहे थे, तब भी पंडित, पुजारी, पोंगापंथी पूजे जा रहे थे। जब जीसस को लोग सूली पर चढ़ा रहे थे, तब भी धर्मगुरु का सम्मान किया जा रहा था।

तुम्हारी बुद्धि जिससे राजी हो जाती है, वह अक्सर धोखा होता है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि वह धोखे की पूरी तैयारी करता है। वह गुरु नहीं, गहरे अर्थ में सिर्फ राजनेता है। राजनेता की कला का सार यही है कि लोग जहां जाना चाहते हैं, वहां जल्दी से उचक कर उनके आगे हो जाता है।

लोग पूरब जा रहे हैं तो वह कहता है पूरब जाना है। लोग पश्चिम जाने लगें तो कहता है, मैं तो सदा कह रहा था कि पश्चिम जाना है और लोगों को समझ नहीं आ पाता कि वह हमारी नजरें परख रहा है, हमारे भाव परख रहा है, हवा का रुख परख रहा है। सद्‌गुरु तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकता,परमात्मा के हिसाब से चलता है। उसके साथ तो जिसे राजी होना हो, उसे ही राजी होना पड़ता है। वह तुम से राजी नहीं होता। समझ लेना, जो तुमसे राजी है, वह तुम्हें बदल नहीं पाएगा।

कई बार ऐसा होता है कि ध्यान में जाने और मंत्रों के उच्चारण के बाद भी मन अन्य बातों की ओर भागता है।

मानसिक ऊर्जा का स्रोत

जैसे किराने की दुकान खुली या नहीं? या आज खाना कौन बनाएगा? पर जब आप खुद के साथ समय बिताने की आदत डाल लेंगे तो मंत्र आपकी मानसिक शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाएंगे और उच्च संस्कारों का निर्माण होगा। आपको अपने मन को इसके अनुकूल बैठाना होगा। अनचाही चीजों के बारे में सोचते रहना मन का स्वभाव होता है। जब भी हम चिंता करते हैं तो हमारा शरीर काफी सारी ऊर्जा खो बैठता है।

ऊर्जा मत खोओ

दो गलत तरह के मंत्रों का उपयोग करने से हम अपनी यह ऊर्जा खो बैठते हैं। पहला है आर्द, जिसका मतलब होता है बार-बार दु:खों को याद करते रहना। दूसरा है रौद्र, जिसका मतलब होता है गुस्से को आने देना। इनका परिणाम यह होता है कि शरीर बीमारियों का शिकार होने लगता है। अपने मन को आर्द और रौद्र से छुटकारा दिलाने के लिए अपनी आध्यात्मिक क्रिया जारी रखें, मंत्रों का उच्चारण करें और ध्यान में जाएं। महर्षि पातंजलि ने योगसूत्रों में कहा है- यदि स्तान संशय अतिरति प्रमाद आलस्य। बीमारी, उत्साह की कमी, शंका, चिंता आदि रुकावटों को दूर करने के लिए एक तत्व अभ्यास का प्रयोग करें। किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करें, उस एक ध्वनि का, एक शब्दांश का लंबे समय तक अभ्यास करें।

मन का विचार

तो जब मन में विचार और मंत्र दोनों चल रहे हों, आपका मन और चैतन्य मंत्रों से भरा होना चाहिए। तब मन चिंताओं से मुक्त हो जाता है क्योंकि एक मंत्र में शक्ति के साथ-साथ एक खास स्पंदन भी होता है। जब उसका उच्चारण किया जाता है, तो वह ऊर्जा में बदल जाता है और आपके चैतन्य को भर देता है। जैसे-जैसे चैतन्य में यह ऊर्जा बढ़ती है, हम स्वयं के और करीब आ जाते हैं और हमारी हर चीज में- जैसे कि हमारे घर में, मन में शरीर और वातावरण में यह ऊर्जा और निश्चयात्मकता फैलती चली जाती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

गौरव गोगोई पाकिस्तान से क्यों ली मदद : सीएम हिमंता

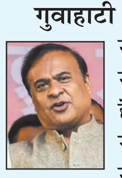

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को दावा किया कि राज्य में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं गौरव गोगोई और पवन खेड़ा के बीच चल रहे पासपोर्ट विवाद में पाकिस्तान से संबंध होने के आरोपों को दोहराया। यह विवाद उनकी पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा से जुड़े दावों को लेकर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि असम में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। अपने हमले को और तेज़ करते हुए, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं गौरव गोगोई और पवन खेड़ा से कथित विदेशी संबंधों के बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा कि आपने एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूह से मदद क्यों ली? हमारे बारे में जो कुछ भी कहा गया है, हम अदालत जाएंगे, लेकिन मेरा आरोप यह है कि पाकिस्तान गौरव गोगोई की मदद क्यों कर रहा है? सरमा ने आगे कहा कि तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई ने इतनी नीच हरकत क्यों की? और आप हमें पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के बारे में क्यों नहीं बताते?

पवार और अठावले समेत राज्य सभा के 19 सदस्यों ने ली शपथ

नईदिल्ली। एनसीपी-एससीपी नेता शरद पवार और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत राज्यसभा के 19 नए सदस्यों ने सोमवार को शपथ ली। राज्यसभा अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन की उपस्थिति में शपथ ली गई। राज्यसभा कक्ष में आयोजित समारोह के दौरान उपसभापति हरिवंश और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित थे। सदन में संबंधित दलों के सदन नेता भी उपस्थित थे। नव निर्वाचित सदस्यों में महाराष्ट्र से पांच, तमिलनाडु से छह, पश्चिम बंगाल से पांच और ओडिशा से तीन सदस्य शामिल थे। महाराष्ट्र स्थित भाजपा इकाई की माया चिंतामन इवानते ने सबसे पहले शपथ ली, उसके बाद श्री पवार ने शपथ ली, जो व्हीलचेयर पर आए थे। रामराव सखाराम वाडकुटे (भाजपा), ज्योति नागनाथ वाघमारे (एसएस) और अठावले (आरपीआई-ए) ने भी उच्च सदन में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए शपथ ली। मनमोहन सामल (भाजपा), संरस मिश्रा (बीजेडी) और दिलीप कुमार राय (निर्दलीय) ने ओडिशा से सदस्य के रूप में शपथ ली।

महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में पड़ी दरार

मुंबई। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव गुट) के बीच 'बैसाखी' वाली टिप्पणी को लेकर तनातनी खुलकर सामने आ गई है। दरअसल, शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में कांग्रेस पर आरोप लगाया गया कि वह क्षेत्रीय दलों को बराबरी का दर्जा देने के बजाय उन्हें बैसाखी की तरह इस्तेमाल करती है। इस टिप्पणी ने कांग्रेस नेताओं को नाराज कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने इस पर कड़ा जवाब देते हुए कहा कि संपादकीय के जरिए पार्टी पर निशाना साधना गठबंधन की भावना के खिलाफ है। उन्होंने सामना के कार्यकारी संपादक और सांसद संजय राउत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे कई बार पत्रकार और राजनेता की भूमिकाओं में भ्रमित नजर आते हैं। सचिन सावंत ने स्पष्ट किया कि गठबंधन राजनीति में सभी दलों की अपनी राय होती है और किसी भी फैसले से पहले आपसी संवाद जरूरी है।

कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा के खिलाफ उतारा प्रत्याशी

मुंबई। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की बारामती सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी के प्रदेश सचिव आकाश मोरे को मैदान में उतारा है। मोरे का मुकाबला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से होगा। मोरे, पूर्व विधायक विजयराव के पुत्र हैं और धनगर समुदाय से संबंध रखते हैं। बारामती सीट, 28 जनवरी को पूर्व उपमुख्यमंत्री और सुनेत्रा के पति अजीत पवार के निधन से बाद से खाली थी। यहां 23 अप्रैल को उपचुनाव होना है। इससे पहले, सुनेत्रा ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को फोन किया और उनसे बारामती विधानसभा क्षेत्र में निर्विरोध उपचुनाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। लेकिन देर शाम कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। एक दिन पहले, सुनेत्रा ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे से समर्थन मांगा था। विपक्षी एनसीपी (एसपी) ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह बारामती क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दिवंगत अजीत पवार के सम्मान में उपचुनाव नहीं लड़ेगी।

मुर्शिदाबाद में मस्जिद निर्माण के चलते चुनावी लड़ाई हुई रोचक

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तीन विधानसभा क्षेत्र (भरतपुर, रेगिनगर और बेलडांगा) 2026 के विधानसभा चुनाव का सबसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से गर्म क्षेत्र बन गए हैं। इसका कारण है रेगिनगर में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद का निर्माण, जिसने मतदाताओं की निष्ठा को बदलने, धार्मिक पहचान को सशक्त करने और अल्पसंख्यक वोटों को विभाजित करने की संभावनाओं को जन्म दिया है। इस मस्जिद की नींव दिसंबर 2025 में टीएमसी के निलंबित विधायक और अब अजयूप पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने रखी थी। भाजपा इसे हिंदू वोट एकजुट करने के लिए राजनीतिक रूप से अमूल्य अवसर मान रही है। पार्टी नेताओं का कहना है बाबरी के नाम पर हर ईंट हिंदू मतदाताओं को जोड़ने में मदद कर रही है। टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में खींच सकते हैं।

असम में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर चौतरफा वार

दिल्ली का शाही परिवार इस बार अपनी हार का शतक लगाएगा : मोदी

बरपेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बरपेटा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार असम की जनता दो बड़े फैसले करने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला, राज्य में भाजपा-एनडीए सरकार की हैट्रिक तय है। वहीं दूसरा, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में बैठा शाही परिवार इस बार अपनी हार का शतक लगाएगा और असम की जनता ही इसे संभव बनाएगी।

रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी दीर्घकालिक विकास की सोच के साथ काम नहीं करती और अल्पकालिक राजनीति के जरिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, जबकि भाजपा दीर्घकालिक दृष्टि के साथ देश के विकास पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में असम में शांति और स्थिरता स्थापित करने पर ध्यान दिया गया और आने वाले वर्षों में राज्य की समृद्धि को और विस्तार दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान के विचारों से संबंध रखने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी दल के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी रवैये की वजह से पाकिस्तान को बार-बार इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। पीएम मोदी ने दावा किया कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तान के पक्ष में रुख अपनाया था। उन्होंने रक्षा और शासन व्यवस्था के क्षेत्र में पार्टी के व्यापक रिकॉर्ड की आलोचना को दोहराया।

प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के रुख ने ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को प्रोत्साहन दिया है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान कांग्रेस ने वही बातें दोहराईं जो पाकिस्तान फैला रहा था। कांग्रेस नेताओं का

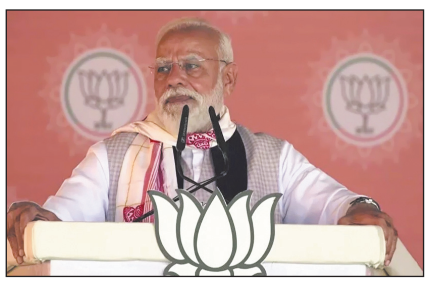

पाकिस्तान से यह संबंध हमेशा से रहा है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी असम में 9 अप्रैल को होने वाले 126 विधानसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन जुटाने के लिए आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आई।

मोदी ने कहा कि कांग्रेस कभी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं जाती। जबकि बीजेपी सरकार, साफ नीयत से जनता को बताती है कि हमने जनता की सेवा के लिए क्या किया। मोदी ने कहा कि 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब धान का एमएसपी मात्र 1,300 रुपए/क्विंटल था। आज धान का एमएसपी करीब 2,370 रुपए/क्विंटल है और असम की भाजपा सरकार अपनी तरफ से भी इसमें वृद्धि करती है। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले के 10 वर्षों में जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब देश के धान किसानों को एमएसपी के सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन 2014 के बाद के 10 वर्षों में धान किसानों को हमारी सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। साफ है कांग्रेस कभी धान किसानों का भला नहीं कर सकती।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए विधानसभा में और संसद में महिलाओं की भूमिका हो, ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तय हुआ है। देश की बहन बेटियों ने 40 साल तक इसका इंतजार किया है। इसलिए जरूरी है 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को ये हक मिले। इसके लिए कानून में संशोधन आवश्यक है। इसलिए 16 अप्रैल से सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है। हमने देश की सभी पार्टियों से इसकी चर्चा की है। हमने सभी से कहा है कि आइए, देश की बहनों बेटियों के हक से जुड़े इस काम को सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं।

मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 60—65 साल के राज में हमारे आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है। सबसे ज्यादा गरीबी आदिवासी क्षेत्रों में रही, हिंसा की बम बंदूक की सबसे बड़ी समस्या आदिवासी क्षेत्रों में रही। देश के आदिवासी समाज को कांग्रेस ने यही सब दिया। कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का साथ दे रही है। कांग्रेस, अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रही है। कांग्रेस असम में ऐसा कानून बनाने की बात भी कर रही है जिसके बाद घुसपैठिया शब्द बोलने वाले को भी जेल हो जाएगी। कांग्रेस, कानून में ही घुसपैठियों को पीड़ित घोषित कर देगी। यहां की जो मूल संतानें हैं, जो जनजातियां हैं उन पर जेल का खतरा मंडरा रहा होगा। हर इंटरव्यू में, अपने भाषण में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ऐसे असम विरोधी कानून की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए भाजपा को दिया गया आपका वोट असम को सुरक्षा देगा, असम की पहचान बचाएगा। प्रधानमंत्री ने भाजपा के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ पार्टी देश सेवा में जुटी है और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। भीड़ का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि बरपेटा की रैली में भारी जनसमूह उमड़ा है और लोगों ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं।

राहुल गांधी ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

दिल्ली से चलती है पुडुचेरी की कमीशन सरकार

पुडुचेरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि पुडुचेरी सरकार दिल्ली से थोपी गई है और यह क्षेत्र की जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उन्होंने भाजपा पर पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में विफल रहने और केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, पुडुचेरी में मतदान 9 अप्रैल को होना है और मतगणना 4 मई को होगी। पुडुचेरी की 30 सदस्यीय विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है।

लॉस्पेट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पुडुचेरी की सरकार पुडुचेरी की जनता की राय नहीं है, बल्कि दिल्ली से थोपी गई है। पूर्ण राज्य का दर्जा हमेशा से एक मुद्दा रहा है, जिसका वादा भाजपा ने किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। भाजपा चाहती है कि पुडुचेरी श्री अडानी के स्वामित्व में रहे। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कराईकल को पहले ही उन्हें बेचा जा चुका है।

उन्होंने प्रशासन पर व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सब जानते हैं कि सभी ठेकों पर 30 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है। सरकार कमीशन एजेंट बन गई है। शराब लाइसेंस का राज चल रहा है, जनता चाहे जितनी भी शिकायत करे, कुछ नहीं होता। वे जनता से तो चोरी करते ही हैं, साथ ही भगवान से भी चोरी करते हैं; कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। राहुल गांधी ने पुडुचेरी के लिए कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की, जिनमें बेरोजगार युवाओं के लिए 2,000 रुपये की मासिक सहायता, 30,000 नए रोजगारों का सृजन, महिलाओं के लिए

मुफ्त बस यात्रा, सरकारी नौकरी पात्रता के लिए आयु सीमा में वृद्धि और प्रत्येक परिवार के लिए 20 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा शामिल है।

उन्होंने विस्तार से बताया कि कांग्रेस गठबंधन सरकार पुडुचेरी के लिए क्या करने जा रही है? हम बेरोजगार युवाओं को 2000 रुपये की मासिक सहायता देंगे, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में 30,000 नए रोजगार सृजित करेंगे और महिलाएं पुडुचेरी की बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी। हम सरकारी नौकरियों में प्रवेश की आयु सीमा को 40 वर्ष तक कम करने जा रहे हैं। पुडुचेरी के प्रत्येक परिवार को 20 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा।

राहुल गांधी ने एलपीजी संकट को लेकर केंद्र पर साधा निशाना

पश्चिम एशिया में तनाव चल रहे है। अब इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी गैस संकट से उसी तरह निपटा है, जैसे उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटा था। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि यह नीति से रहित, केवल बड़ी-बड़ी घोषणाओं से भरा है। इसका पूरा बोझ गरीबों पर डाल दिया है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सवाल उठाया कि हर संकट में सबसे पहले गरीब ही क्यों मरते हैं? वहीं, लोगों से चुप न रहने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने एक्स के एक पोस्ट में कहा, मोदी जी ने कहा था हम एलपीजी गैस संकट को उसी तरह संभालेंगे जैसे हमने कोविड को संभाला था। और वास्तव में, उन्होंने ठीक वैसा ही किया। बिल्कुल कोविड की तरह-नीति का अभाव, बड़ी-बड़ी घोषणाओं से भरा हुआ, और सारा बोझ गरीबों पर डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 500-800 रुपये की मजदूरी कमाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए खाना पकाने की गैस पूरी तरह से महंगी हो गई है। उन्होंने कहा कि रात में घर लौट रहे एक मजदूर के पास चूल्हा जलाने के लिए भी पैसे नहीं होते। उन्होंने आरोप लगाया कि परिणाम क्या हुआ? शहर छोड़कर गांव भाग जाना। कपड़ा मिलों और कारखानों की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले मजदूर आज खुद टूटने की कगार पर हैं।

उन्होंने आगे कहा, वस्त्र क्षेत्र पहले से ही आईसीयू में है। विनिर्माण क्षेत्र सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। और इस संकट की जड़ कहां है? उस कूटनीतिक चूक से - जो वार्ता की मेज पर हुई - जिसे सरकार आज तक स्वीकार करने से इनकार करती है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जब अहंकार नीति बन जाता है, तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, मजदूर पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, उद्योग बर्बाद हो जाते हैं और पूरा देश दशकों पीछे चला जाता है।

खेल
प्रमुख समाचार

संजू सैमसन के बचाव में उतरे सीएसके के मुख्य कोच फ्लेमिंग

बेंगलुरु। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने आपीएल 2026 में संजू सैमसन के के अब तक के खराब प्रदर्शन को खास तवज्जों नहीं दी और कहा कि यह विकेटकीपर बल्लेबाज टीम के माहौल में ढलने की प्रक्रिया से गुजर रहा है तथा रन बनाने और टीम की सफलता में योगदान देने के लिए बेताब है। सीएसके को रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से 43 रन से हार का सामना करना पड़ा। यह लगातार तीसरा मैच था जिसमें सैमसन का बल्ला नहीं चला। उन्होंने अब तक तीन मैच में छह, सात और 9 रन बनाए हैं।

फ्लेमिंग ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब आप किसी फ्रेंचाइजी (इस मामले में राजस्थान रॉयल्स) की तरफ से लंबे समय से खेल रहे हों तो फिर किसी नई टीम के माहौल में ढलने में समय लगता है। भले ही वह शायद काफी सहज महसूस करता हो, फिर भी अपनेपन की भावना बनी रहती है और वह इस टीम के माहौल में ढलने की प्रक्रिया से गुजर रहा है।

फ्लेमिंग ने कहा कि केरल का यह खिलाड़ी लय हासिल करने के लिए बेताब है। उन्होंने कहा, टीम (सीएसके) में पांच या छह बदलाव हुए हैं। मैदान से इतर कुछ काम करना बाकी है ताकि टीम के आपसी संबंध और मजबूत हो सकें। लेकिन वह टीम में बहुत अच्छे से घुल-मिल गया है। फ्लेमिंग ने कहा, वह रन बनाने और सीनियर खिलाड़ियों के साथ योगदान देने के लिए बेताब हैं। हमने विश्व कप में उसके प्रदर्शन में देखा कि जब वह लय में आ जाता है तो वह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए संजू को पीले रंग की जर्सी में अपना सफर तय करने में हमारी तरफ से पूरा समर्थन मिलेगा। फ्लेमिंग ने कहा कि आयुष म्हात्रे जैसे युवा खिलाड़ियों के साथ धैर्य रखने की जरूरत है ताकि वे निरंतरता हासिल कर सकें।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स निचले स्तर से 1400 अंक चढ़ा, निफ्टी 22968 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों से पॉजिटिव रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन यानी सोमवार (6 अप्रैल) को सपाट खुलने के बाद जोरदार बढ़त के साथ बंद हुए। ट्रंप की रविवार को धमकी के बीच निवेशक शुरूआती कारोबार में सतर्क नजर आये। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ 73,477 अंक पर खुला। शुरूआती मिनटों में कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिलने के बाद इंडेक्स में गिरावट बढ़ गई। कारोबार के दौरान यह 72,728 अंक तक फिसल गया था। अंत में 787.30 अंक या 1.07 प्रतिशत बढ़कर 74,106.85 पर बंद हुआ। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी-50 भी सपाट रुख के साथ 22,780 पर खुला। कारोबार के दौरान यह 22,542 अंक के लो और 22,998 अंक के हाई तक गया। अंत में 255.15 अंक या 1.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,968.25 पर बंद हुआ।

एनएमडीसी ने लौह अयस्क के दाम 11.1% तक बढ़ाए

नई दिल्ली। सरकारी स्वामित्व वाली एनएमडीसी ने लौह अयस्क के दामों में 11.1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है। कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी ने बताया कि नई कीमतें पांच अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गईं। कंपनी सूचना के अनुसार बैलाडीला खदानों (छत्तीसगढ़) से उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाले बायला लंप (65.5 प्रतिशत लौह अंश) के दाम में 10.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वहीं बायला फाइंस (64 प्रतिशत लौह अंश) के दाम 11.1 प्रतिशत बढ़ाए गए हैं। बायला फाइंस 10 मिलीमीटर से कम आकार का उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क उत्पाद है जो बैलाडीला क्षेत्र की खदानों से प्राप्त होता है। एनएमडीसी ने हाल ही में समाप्त वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 5.3 करोड़ टन लौह अयस्क का उत्पादन किया।

बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स ने घटाया निफ्टी का टारगेट

वाशिंगटन। मिडिल ईस्ट में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने सोमवार (6 अप्रैल) को भारतीय शेयर बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। शुरुआती सपाट शुरुआत के बाद कारोबार के दौरान बिकवाली हावी हो गई, जिससे निवेशकों की धारणा कमजोर पड़ती दिखी, जिससे निवेशकों की धारणा कमजोर पड़ती दिखी। इस बीच, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स के बाद अब बैंक ऑफ अमेरिका (BofA) ने भी भारतीय बाजार को लेकर सतर्क रुख अपनाया है। BofA ने दिसंबर 2026 तक के लिए निफ्टी का लक्ष्य 29,000 से घटाकर 26,200 कर दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि महंगाई और सुस्त ग्रोथ के चलते कंपनियों की कमाई पर दबाव बढ़ सकता है। BofA ने वित्त वर्ष 2027 के लिए निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ का अनुमान घटाकर 8.5% कर दिया है, जो पहले के अनुमानों से काफी कम है।

10 अप्रैल से टोल पर कैश बंद, फास्टैग अनिवार्य

नईदिल्ली। हाईवे टोल प्लाजा पर 10 अप्रैल से नकद भुगतान बंद हो जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर पूरी तरह डिजिटल टोल कलेक्शन अनिवार्य कर दिया है। इस बदलाव का असर रोजाना सफर करने वालों के खर्च और भुगतान के तरीकों पर पड़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए टोल नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है। 10 अप्रैल से सभी टोल भुगतान डिजिटल माध्यम से ही होंगे, मुख्य रूप से फास्टैग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से। यह कदम भारत की टोल प्रणाली को और सख्त बनाता है, जो पहले ही फास्टैग आधारित भुगतान की ओर काफी हद तक बढ़ चुकी है।

आदिवासी खेल : नई प्रतिभाओं की तलाश में एक सार्थक पहल

रवींद्र चोपड़े

रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के उद्घाटन पर्व पर आई मैरी कोम ने प्रेस कांफ्रेंस में तथ्यात्मक बयान दिया। छह बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता इस मुक्केबाज का कहना था कि ट्राइबल्स (आदिवासियों) में खेलों का हुनर जन्मजात होता है। बस उन्हें अवसर की दरकार है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में यह बात सच साबित हुई। इस आयोजन में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए तकरीबन ढाई हजार खिलाड़ियों ने कई खेलों में अपनी प्रतिभा दुनिया को दिखाई। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में 106 तमगों का बंटवारा हुआ, जिनमें से 23 स्वर्ण, आठ रजत तथा सात कांस्य पदक लेकर कर्नाटक ने तालिका में अव्वल स्थान हासिल किया। 21 स्वर्ण के साथ ओडिशा ने दूसरा जबकि 16 स्वर्ण पदकों के साथ झारखंड ने तीसरा स्थान अर्जित किया।

इस आयोजन के लिए भारत सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) की यकीनन प्रशंसा की जानी चाहिए। आदिवासी बच्चों में मौजूद खेल प्रतिभाओं को ढूंढ़कर उन्हें ओलंपिक जैसे खेलों के महाकुंभ में पदक जीतने के काबिल बनाने में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

अगर यह प्रयास सार्थक दिशा में बढ़ता रहा तो आनेवाला कल भारतीय खेलों में उन लोगों का होगा जो आज आदिवासी होने के कारण उपेक्षित हैं। भारत में संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति (शेड्यूल ट्राइब्स-एसटी) के तहत उस समुदाय को आदिवासी का दर्जा दिया गया है जो पीढ़ियां गुजर जाने के बावजूद समाज की मुख्य धारा से दूर हैं, भौगोलिक रूप से अलग-थलग हैं,

जंगलों-पहाड़ों में घूमते हैं और जिनकी संस्कृति, भाषा तथा जीवनशैली भिन्न हैं। भारत में इनकी आबादी नौ फीसदी के करीब (लगभग 11 करोड़) बताई जा रही है और इनमें तकरीबन सभी प्रदेशों की 700 से अधिक जनजातियां शामिल हैं। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों समेत मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर में आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं।

इतिहास के पन्नों में झांकें तो असल में आदिवासी ही भारत के मूल नागरिक हैं और यह सप्रमाण साबित भी हुआ है। बाद में आक्रांताओं के सामंती रवैये के कारण इस विशाल जनसमुदाय को मुख्यधारा से विलग कर दिया गया। हालांकि अब संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत आदिवासियों को विशेष सुरक्षा दी गई है।

नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिलने से आदिवासियों को प्रगति का बोध हुआ है। सो, 11 करोड़ आदिवासियों में यदि तलाश शिद्दत से की जाए तो कई खेल प्रतिभाएं सामने आएंगी। एक खिलाड़ी बनने के लिए जरूरी शारीरिक क्षमता, शारीरिक रचना आदिवासियों में प्रकृति प्रदत्त है।

हम देखते हैं कि मेलों में, बाजार में या सड़कों पर जो आदिवासी बच्चियां रस्सियों पर, रिंग पर कितनी सफाई से अपना खेल दिखाती हैं, उन्हें अगर उचित तरीके से तराशा जाए तो जिम्नास्टिक, दौड़, तैराकी जैसे ताकत के खेलों में भारत पदकों का दावेदार बन सकता है। आदिवासियों की प्रकृत्ति प्रदत्त क्षमताओं को यदि भुनाया जाए तो क्यों नहीं उसैन बोल्ट जैसा दुनिया का सबसे तेज धावक भारत में तैयार होगा।

हमारा देश 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। ओलंपिक में पदकों के मामले में हमारा रिकॉर्ड सुहाना नहीं है और सौ करोड़ से भी अधिक आबादी के बावजूद तमगे हासिल करने में भारत पर फिसड्डीपन का आरोप लगता रहा है।

तमगे तभी मिलेंगे जब खेल प्रतिभाओं को चुन-चुनकर सामने लाया जाएगा और इस दिशा में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स सार्थक पहल साबित हो सकती है। इसका लाभ निश्चित तौर 2036 ओलंपिक में मिलेगा। इस ओलंपिक की शान तभी बढ़ेगी जब भारत मेजबान होने के नाते पदक तालिका में शीर्ष 10 में शामिल रहेगा।

प्रदेश की धरती के कण-कण में बसे हैं भगवान श्रीरामः मुख्यमंत्री साय

कुनकुरी के सालियाटोली में आयोजित भव्य संगीतमय श्रीराम कथा महोत्सव में शामिल हुए।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पावन अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य संत चिन्मयानंद बापूजी को सादर नमन करते हुए कहा कि आज कुनकुरी की यह पावन धरा धन्य हो गई है। उन्होंने कहा कि सालियाटोली का यह स्टेडियम राम कथा के रसपान से साक्षात राम का धाम बन गया है और चारों ओर 'जय राम' की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो उठा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु राम का छत्तीसगढ़ से अत्यंत गहरा संबंध है। यह माता कौशल्या की पावन धरती है और भगवान राम का ननिहाल है, जहाँ वे भांजे के रूप में घर-घर में पूजे जाते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य क्षेत्र एवं छत्तीसगढ़ के जंगलों में बिताया, जिससे यहाँ के कण-कण में राम की उपस्थिति अनुभव होती है। वनवास काल से जुड़े सीता रसोई जैसे अनेक पवित्र स्थल आज भी इस भूमि की आध्यात्मिक विरासत के सा हैं। उन्होंने कहा कि यह हम सभी का सौभाग्य है कि हम उस कालखंड में जीवन जी रहे हैं, जब अयोध्या में भगवान राम की पुनः प्रतिष्ठा हुई है। राम की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे भारत को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प से संभव हो सका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संकल्प लिया था कि प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। इसी भावना के अनुरूप राज्य सरकार ने गठन के साथ ही रामलला दर्शन योजना प्रारंभ की, जिसके माध्यम से अब तक लगभग 42 हजार श्रद्धालु अयोध्या धाम में भगवान राम के दर्शन कर चुके हैं।भगवान राम भारतीय जनमानस के कण-कण में विराजमान हैं। जांजगीर क्षेत्र में रामभक्ति का विशेष स्वरूप देखने को मिलता है, जहाँ रामनामी समुदाय के लोग अपने रोम-रोम में राम का नाम बसाए हुए हैं और अपनी आस्था के प्रतीक स्वरूप अपने शरीर पर 'राम-राम' का गोदना अंकित कराते हैं। उन्होंने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल और 100 टन से अधिक हरी सब्जियां अयोध्या भेजी गई थीं। यह विशेष भोग ननिहाल के प्रेम और 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात प्रभु की स्थापना के उपलक्ष्य में समर्पित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ से गई डॉक्टरों की टीम एवं मेडिकल स्टाफ ने अयोध्या में रामभक्तों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्ति पर गृहमंत्री विजय शर्मा का हुआ भव्य ऐतिहासिक अभिनंदन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सहित देश के लिए ऐतिहासिक क्षण तब आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च को सदन में शस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति की घोषणा की। लगभग चार दशकों से इस समस्या से जूझ रहे छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा के दृढ़ संकल्प, रणनीति और सतत प्रयासों से यह बड़ी सफलता हासिल की।

इस अभियान में भारतीय सेना, पुलिस और समस्त सशस्त्र बलों के जवानों के अदम्य साहस, समाज की जागरूक भागीदारी, राजनीतिक नेतृत्व की इच्छाशक्ति, पत्रकार बंधुओं की भूमिका और सबसे बढ़कर बस्तर के नागरिकों के सहयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभी के समुचित प्रयासों से ही सशस्त्र नक्सलवाद का अंत संभव हो सका और अब बस्तर में खुशहाली की नई शुरुआत हो रही है। सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ बनने के बाद उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र कवर्धा पहली बार पहुंचे। जहां पर स्थानीय महामाया चौक में कवर्धा के लोगों ने उनके लिए भव्य ऐतिहासिक नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया। जिसमें हजारों की संख्या में लोग बाजा-गाजा, ढोल-नगाड़ों के साथ शामिल हुए, पूरे शहर में जश्न का वातावरण नजर आया। सभी को गर्व था कि कभी नक्सल प्रभावित कबीरधाम जिले के साथ अब पूरे छत्तीसगढ़ से भय और आतंक को दूर करने में उनके अपने माटी पुत्र का बड़ा योगदान रहा है।

इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज, यादव समाज, ठाकुर समाज, कुर्मी समाज, साहू समाज, सतनामी समाज, निर्मलकर समाज, गुप्ता समाज, अहिरवार समाज, लोधी समाज, पटेल समाज, गोंड समाज, केसरवानी गुप्ता समाज, सेन समाज, गंधर्व समाज, स्वर्णकार समाज, जैन समाज, वैष्णव समाज सहित सभी समाजों ने भव्य रैली का स्वागत कर इस असंभव से लगने वाले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी।

जहां स्थानीय जिला प्रेस क्लब, यूथ क्लब, हरीतिमा परिवार, प्राइवेट स्कूल संघ, नाथ योगी समाज, फाइटर क्लब, जिला क्रिकेट संघ, ज्वाइन हैंड ग्रुप, ट्रक मालिक संघ, पतंजलि योग समिति, सीनियर सिटीजन समिति एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भी शामिल होकर उनका अभिनंदन किया।

महादेव घाट रायपुरा में 5वीं अखिल भारतीय वॉलीबॉल स्पर्धा 2026 का समापन

पुरुष वर्ग में उत्तरप्रदेश और महिला वर्ग में राजस्थान चैंपियन

रायपुर। महादेव घाट स्थित हटकेश्वरनाथ वॉलीबॉल मैदान में आयोजित 5वीं अखिल भारतीय वॉलीबॉल स्पर्धा 2026 के पुरुष वर्ग के खिताब पर उत्तरप्रदेश और महिला वर्ग में राजस्थान ने खिताब पर कब्जा जमाया। तीन दिनों तक चली प्रतियोगिता के अंतिम दिन पुरुष और महिला वर्ग का फाइनल मैच खेला गया।

महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला राजस्थान और रायपुर के बीच खेला गया। राजस्थान की टीम ने रायपुर को लगातार तीन सेटों में 3-0 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। राजस्थान की महिला खिलाड़ियों ने पूरे मैच में शानदार तालमेल, मजबूत डिफेंस और प्रभावशाली आक्रमण का परिचय दिया। मुकाबले में राजस्थान ने पहले सेट को 25-09, दूसरे सेट को 25-15 और तीसरे सेट को 25-07 से जीतते हुए एकतरफा मैच अपने नाम किया। रोमांचक मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम ने हटकेश्वरनाथ वॉलीबॉल क्लब रायपुर को 2-0 से पराजित कर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। उत्तर प्रदेश की टीम ने अपने अनुभव, बेहतर समन्वय और आक्रामक खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला सेट 25-12 तथा दूसरा सेट 25-19 से जीत लिया।

अंत्योदय के संकल्प के साथ विकसित भारत की ओर अग्रसर भाजपाः बृजमोहन

रायपुर। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर अपने कार्यालय में पार्टी का ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ-साथ समस्त देशवासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और आज यह विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन चुका है। उन्होंने स्मरण किया कि उस समय भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। मुंबई में आयोजित पहले अधिवेशन में अटल जी द्वारा दिया गया उद्घोष- अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगाआज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्णतः साकार होता दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 'अंत्योदय' के संकल्प के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वर्ष 1951 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में स्थापित जनसंघ के जिन उद्देश्यों को लेकर यात्रा प्रारंभ हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना हो या धारा 370 का उन्मूलन कर देश की एकता और अखंडता को सशक्त बनाना।

छत्तीसगढ़ बनेगा मखाना हब : नेताम

रायपुर। छत्तीसगढ़ मखाना हब बनेगा। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम आज रायपुर जिले अंतर्गत आरंग के लिंगाडीह में मखाना सेंटर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि रायपुर, धमतरी, गरियाबंद और बालोद क्षेत्र सहित प्रदेश में मखाना की खेती की संभावना अत्यधिक है। उन्होंने मखाना उत्पादन क्षेत्रों व जिलों को सर्किट के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने मखाना खेती के विस्तार की संभावनाओं की जानकारी ली और कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मखाना हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंत्री को जानकारी दी कि आरंग क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों में लगभग 50 से 60 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती की जा रही है, जहां ग्रेड-6 गुणवत्ता का मखाना उत्पादन हो रहा है। इसकी बाजार में अच्छी मांग होने से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रायपुर, धमतरी, गरियाबंद एवं बालोद जिलों को जोड़ते हुए मखाना सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण एवं विपणन की समेकित व्यवस्था तैयार की जाएगी, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके।

दौरे के दौरान मंत्री ने मखाना सेंटर में तैयार उत्पादों का अवलोकन किया तथा स्वयं मखाना चखकर उसकी गुणवत्ता की सराहना की। केंद्र सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, खाद्य प्रसंस्करण एवं मिलेट्स और पारंपरिक फसलों को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गठित मखाना बोर्ड की योजनाओं से राज्य के किसानों को जोड़ते हुए तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार के समन्वित प्रयासों से मखाना किसानों के लिए आय का नया विकल्प बनेगी।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भाजपा सिद्धांतविहीन पार्टी, लोकतांत्रिक चरित्र नहींः बैज

रायपुर। भाजपा के स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतविहीन पार्टी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जब इस पार्टी का गठन किया गया तब बड़े-बड़े दावे किये गये कि यह देश भक्त पार्टी है, लेकिन सारे दावे झूठे साबित हुए। यह पार्टी सत्ता हासिल करने के लिये किसी भी स्तर पर जा सकती है। विपक्षी दलों के विधायकों का खरीद फरोख्त कर इसने अनेकों राज्यों में जनादेश का अपमान किया है। धनबल का उपयोग कर भाजपा ने लोकतंत्र को कमजोर करने के अनेकों प्रयास किये है। भाजपा का मूल रूप से अलोकतांत्रिक चरित्र की पार्टी है। वह लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती है। भाजपा जब केंद्र में सत्ता में आई तो केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष को प्रताड़ित और डराने का काम किया। विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करना यह पार्टी का मूल चरित्र है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव कार्य में लगाती है तो देवतुल्य बताती है लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है अपने कार्यकर्ताओं का शोषण करती है और कार्यकर्ताओं का दोहन करती है और कार्यकर्ताओं को हार का जिम्मेदार ठहराया जाता है। भाजपा के लिए कार्यकर्ता उसके झूठे एजेंडे को प्रचारित करने का साधन मात्र है।

थानों में एफआईआर नहीं लिखा जा रहाः शुक्ला

रायपुर। सरकार प्रदेश की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था को संभाल तो पा नहीं रही है, अब अपनी गलती छुपाने सरकार थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रही। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बढ़ते अपराधों में कमी दिखाने थानों में एफआईआर नहीं लिखा जा रहा, इस कारण पीड़ित को न्याय मिलने की संभावना खत्म हो गयी तथा अपराधियों के हौसले बुलंद हो गये है। अपराध घटित होने के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर अपराधों की संख्या में कमी होने के प्रयास में लगी है ताकि सरकार अपनी पीठ थपथपा पाये। आम आदमी, सरकार और पुलिस के इस रवैये से परेशान हो गया है। चोरी, जालसाजी, मारपीट तथा प्रताड़ना और साइबर ठगी जैसे मामलों में अब राज्य में एफआईआर कराना बहुत कठिन हो गया है। सरकार दो साल में राज्य की कानून व्यवस्था सुधार पाने में पूरी तरह विफल साबित हो चुकी है। लूट, हत्या, बलात्कार, चाकूबाजी, नशे की तस्करी जैसे अपराधों के कारण प्रदेश का आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा, बढ़ती घटनाओं के कारण हो रही बदनामी को रोकने और अपना रिकार्ड सही बताने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं करना जनता पर अत्याचार है। इसके पहले भी जब रमन सरकार थी।

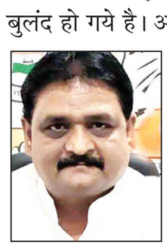

सीजीपीएससी परीक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहींः ठाकुर

रायपुर। सीजीपीएससी परीक्षा को लेकर सरकार और आयोग गंभीर नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि चुनाव के समय राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षा को संघ लोकसेवा आयोग की तर्ज पर कराने का दावा करने वाली भाजपा सरकार राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षा की समय सारणी व्यवस्थित नहीं बनावा पा रही है। परीक्षार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में मात्र 51 दिन का ही अंतराल दिया गया है जबकि पिछले वर्ष यह 104 दिन का था। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष राज्य सेवा परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम 25 मार्च 2026 को जारी किया गया और मुख्य परीक्षा 16, 17, 18, 19 मई 2026 को आयोजित की जाने वाली है तो क्या वजह की अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए इतना कम समय मात्र 51 दिन का समय दिया गया है जबकि पिछले वर्ष के राज्य सेवा परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम और मुख्य परीक्षा के बीच 104 दिन का गैप पीएससी परीक्षा दिलाने वाले अभ्यर्थियों को दिया गया था। इसके पीछे क्या वजह है? क्या युवाओं का हितैषी होने की दावा करने वाले सरकार बताएगी? क्या छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग अध्यक्ष कारण बतायेंगे।

राशन दुकानों में पांच माह से राशन नहीं मिल रहा हैः वंदना

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार 3 महीने का चावल एक साथ देकर चावल उत्सव मनाने जा रही है। अभी तक जितने चावल की जरूरत है उसका 30 प्रतिशत भी चावल राशन दुकानों में नहीं पहुंचा है। 31 लाख उपभोक्ताओं का राशन कार्ड केवाईसी के नाम पर काट दिया। अब चावल उत्सव मनाने का ढकोसला कर रहे है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पिछले पांच महीने से सरकार राशन दुकानों को नियमित राशन तो पहुंचा नहीं पायी है। पांच माह से राशन कार्डधारियों को चावल नहीं मिल रहा है और सरकार तीन महीने का चावल एकमुश्त देने का ढिंढोरा पीट कर चावल उत्सव मनाने जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि अभी तक दुकानों में मात्र 30 प्रतिशत चावल ही उपलब्ध है, जब दुकानों तक चावल नहीं पहुंच पाया है तो उपभोक्ता को कैसे चावल देगी सरकार? प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार नहीं चाहती की सभी को राशन देना पड़े, इसलिए केवाईसी का बहाना कर राशन वितरण रोक दिया गया है। 31 लाख उपभोक्ताओं के राशन कार्ड केवाईसी के नाम पर काट दिया गया। सरकार बनने के बाद सभी राशन कार्ड नए सिरे से बनाए गए थे।

पृथक कॉलम नहीं होना, पिछड़ों के साथ अन्याय : साहू

रायपुर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने आगामी डिजिटल जनगणना के लिए निर्धारित 33 बिंदुओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से कॉलम नहीं होने पर पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए दोहरा मापदंड अपना रही है। पिछड़े समाज के विकास की बात करने वाली केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार आज इस मामले में असहाय क्यों नज़र आ रही है, क्या पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है सरकार? राजपत्र के बिंदु क्रमांक 12 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्पष्ट कॉलम दिया गया है, लेकिन ओबीसी वर्ग की गणना के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। समाज के साथ अन्याय है। बिना पृथक कॉलम के ओबीसी वर्ग की सही संख्या कैसे सामने आएगी? पिछड़ों को उनके अधिकार से वंचित रखने की सरकार की साजिश है। भारत देश एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है जिसे केंद्र की भाजपा सरकार मिटाने पर तुली हुई है। वहीं राष्ट्रीय जनगणना 2027 के 33 बिंदु वाले कालम में ओबीसी वर्ग की पृथक उल्लेख नहीं होने से नाराजगी व्यक्त करते हुए सर्व छत्तीसगढ़िया समाज एससी एसटी ओबीसी महासंघ ने प्रधानमंत्री के नाम से कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है।

नए वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना एवं नवीन व्यय प्रस्तावों की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय को 80% किए जाने का लक्ष्य

रायपुर। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभाकक्ष में गत वर्ष के आय-व्यय एवं नए वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा कुल बजट का 68 प्रतिशत व्यय किया गया है। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु जो बजट आंबटित किया जाता है उसका पूर्ण लाभ हितग्राही वर्ग को मिलना चाहिए। इसके लिए वर्ष के प्रारंभ से ही एक कार्ययोजना बनाकर उसपर अमल किया जाए। इस हेतु सभी प्रभारी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय-सीमा में कार्य संपादित करना चाहिए। श्री बोरा ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय को 80 प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य दिया है।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व एवं मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में विभाग प्रगति ओर अग्रसर है। विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2025-26 में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हेतु 732 करोड़, 21 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु 915 करोड़ तथा अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत 170 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, यह विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो आगामी दो वर्षों में इन सभी कार्यों के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ के विकास को गति मिलेगी। बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के अलावा आदिम जाति अनुंसधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास तथा छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत आय-व्यय की भी समीक्षा की गई। बैठक में संयुक्त सचिव श्री बी.के.राजपूत, श्री अनुपम त्रिवेदी, वित्त नियंत्रक श्री लाजरूस मिंज, अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री आर.एस.भोई, उपायुक्त श्रीमती गायत्री नेताम, श्री प्रज्ञान सेठ, श्री एल.आर.कुर्रे, श्री विश्वनाथ रेडडी, श्रीमती मेनका चंद्राकर, कार्यपालन अभियंता श्री त्रिदीप चक्रवर्ती सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री देवांगन ने कसनिया में 33/11 केवी नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र का शुभारंभ

रायपुर। प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कटघोरा के कसनिया में नवनिर्मित 33/11 केवी उपकेंद्र का आज विधिवत लोकार्पण किया गया। वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम, सार्वजनिक उपक्रम तथा आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने उपकेंद्र का शुभारंभ किया।कार्यक्रम में कटघोरा विधायक श्री प्रेमचंद पटेल तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री भीम सिंह कंवर सहित वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। यह उपकेंद्र 1 करोड़ 82 लाख रुपये की लागत से निर्मित किया गया है तथा इसकी स्थापित क्षमता 3.15 एमवीए है। उपकेंद्र के प्रारंभ होने से कटघोरा, कापूबहरा, सुतर्रा, मोहनपुर, अमरपुर, घूँचापुर, दादर, लखनपुर, राल सहित कटघोरा नगर के 4 वार्डों के लगभग 5,000 से अधिक उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

पूर्व में एकमात्र सबस्टेशन पर बढ़ते लोड के कारण बार-बार होने वाली ओवरलोडिंग एवं तकनीकी बाधाओं से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। नए उपकेंद्र से न केवल विद्युत आपूर्ति में निरंतरता रहेगी बल्कि तकनीकी समस्याओं का तत्काल निराकरण भी संभव हो सकेगा।

मुख्य अतिथि मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपकेंद्र कटघोरा क्षेत्र के विकास में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने लोगों से विभागीय योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने का आग्रह किया।कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने नवीन उपकेंद्र को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया और आमजन से सूर्यघर मुफ्त बिजली बिल योजना अपनाने की अपील की।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.